



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

No. 167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2003/आषाढ़ 13, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2003/ASADHA 13, 1925

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2003

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित शहतूती कच्चे रेशम (बिना बटा हुआ) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 14/28/2002-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. प्रक्रिया

1. प्रारंभिक जांच परिणामों के पश्चात् नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित शहतूती कच्चे रेशम के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में 20.12.2002 की अधिसूचना के द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित किया तथा हितबद्ध पार्टियों से प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया ;

(ख) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति अग्रेषित की और उन्हें उक्त परिणामों पर अपने विचार यदि कोई हों, पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया ;

(ग) इस सुनवाई में 4 दिसंबर, 2002 को घरेलू उद्योग, चीन के निर्यातकों के सलाहकार तथा चीन के दूतावास (वाणिज्यिक परामर्शदाता कार्यालय) ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता निर्दिष्ट

प्राधिकारी ने की। चीन के निर्यातकों के उत्तर में मुख्य कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया और अपेक्षित आंकड़े/सूचना मांगी गई थी।

(घ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षों को अपने विचारों को मौखिक रूप में 3.3.2003 को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग, चीन के निर्यातकों, आयातकों, उपयोक्ता उद्योग तथा चीन के दूतावास ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। पार्टियों को प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और उनका खंडन, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ;

(ङ.) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उपलब्ध करवाई थीं।

(च) याचिकाकर्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रारंभिक जांच परिणामों और/या इन परिणामों में उचित ढंग से विचार किया गया है ;

(छ) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन परिणामों के लिए विचारित तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकट किया गया और उन पर प्राप्त टिप्पणियों (केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत) पर इन परिणामों में विचार किया जाएगा।

(ज) मौखिक सुनवाई के समय, निर्यातकों से घरेलू उद्योग के साथ समुचित क्षतिरहित निर्यात कीमत पर बातचीत करने के लिए कहा गया और कीमत वचनबद्धता पर विचार किया। घरेलू उद्योग ने ' ' यूएस डालर + मूल सीमाशुल्क की क्षतिरहित कीमत का प्रस्ताव किया जो चीन के निर्यातकों को मान्य नहीं था। चीन की कंपनियों ने ' ' यू एस डालर + सीमाशुल्क की क्षतिरहित कीमत के रूप में पेशकश की जो घरेलू उद्योग को स्वीकार्य नहीं थी।

(झ) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शहतूती कच्चे रेशम (बिना बटा हुआ) के पाटित आयात के विरुद्ध 17 जुलाई, 2002 की सार्वजनिक सूचना के द्वारा इस जांच को शुरू किया।

(ञ) यह जांच 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 (12 मास) तक की अवधि के लिए थी।

(ट) पाटन्सरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 6 के पैरा 7 के अनुसरण में मौके पर जांच की क्रियाविधियां अनुबंध- 1 में कहा गया है कि " चूंकि मौके पर जांच करने का मुख्य प्रयोजन दो गई सूचना को सत्यापित करना अथवा और ब्यौरे प्राप्त करना है, यह तभी की जानी

चाहिए जब प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त हो जाए " अतः मौके पर जांच का प्रयोजन प्राधिकारी के पास पहले से उपलब्ध आंकड़ों का सत्यापन करना है न कि प्रारंभिक आंकड़े एकत्र करना है। इन जांचों में निर्यातकों के उत्तर व्यापारिक कंपनियों द्वारा दिए गए थे न कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा और ये संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के मूल आंकड़े तथा घरेलू बिक्रियां कारोबार के बारे में त्रुटिपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त, चेगंडू टियांन्यू द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में कमियां चीन जनवादी गणराज्य को प्रभावित करने वाले सार्स के भयंकर खतरे के कारण इन जांचों में सत्यापन की शर्त के अधीन नहीं होंगी।

(ठ) इस अधिसूचना में *** चिह्न से हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अधीन प्राधिकारी ने इसे गोपनीय ही माना है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

2. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद शहतूती कच्चा रेशम (जो बटा हुआ नहीं है) जो 2ए ग्रेड तथा इससे कम है तथा जो चीन जनवादी गणराज्य के मूल का अथवा वहां से निर्यातित है।

शहतूती कच्चा रेशम (जो बटा हुआ नहीं है) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 50 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं० 50.02 तथा आईटीसी (एचएस) कोड 50020001 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और मौजूदा जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

ग. समान वस्तुएं

3. यह प्रमाणित करने के लिए कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित शहतूती कच्चा रेशम (जो बटा हुआ नहीं है) चीन से निर्यातित कच्चे रेशम के समान वस्तु है, प्राधिकारी द्वारा तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य तथा उपयोग और टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं पर विचार किया गया है।

प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि इस बात का खंडन करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित शहतूती कच्चे रेशम (जो बटा हुआ नहीं है) में आयातित सामग्री से अत्यधिक मिलती जुलती विशेषताएं हैं और यह संबद्ध देश से आयातित शहतूती कच्चे रेशम द्वारा वाणिज्यिक तथा तकनीकी दोनों रूपों में प्रतिस्थापनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित शहतूती

कच्चे रेशम (जो बटा हुआ नहीं है) को नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर चीन जनवादी गणराज्य से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

घ. घरेलू उद्योग

4. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अपनी एसोसिएशनों के माध्यम से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित सभी ऑटेज/फाइलेचर/मल्टीएंड सिल्क रीलर्स तथा किसानों की ओर से यह याचिका दायर की है, जिनके ब्यौरे, जो याचिका में दिए गए हैं, निम्नानुसार हैं-

- क) ऑल सिल्क रीलर्स एसोसिएशन, ककून मार्किट, कोलार के निकट-563101, कर्नाटक
 - ख) रामनगरम सिल्क रीलर्स वैल्फेयर एसोसिएशन, रामनगरम, बंगलौर (ग्रामीण), कर्नाटक
 - ग) कोलार सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, कोलार
 - घ) दि प्रोग्रेसिव सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, सिदलाघट्टा-562105
 - ड.) कर्नाटक स्टेट मल्टी एंड सिल्क रीलर्स वैल्फेयर एसोसिएशन (रजि०), मेन रोड़, कुमाडन मौहल्ला, रामनगरम-571511, बंगलौर (ग्रामीण), कर्नाटक
 - च) तमिलनाडु स्टेट मल्टी एंड रीलर्स एसोसिएशन, नं० 61-ए, कृष्णागिरि मेन रोड़, गवर्मेट ककून मार्किट के सामने, धर्मपुरी-636701
 - छ) दी पालाकोड सिल्क रीलर्स एसोसिएशन, पालाकोड-636808 (तमिलनाडु)
 - ज) कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कोयम्बतूर-641014
- (टी एन)

झ) धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट सिल्क रीलर्स एसोसिएशन 10/81-सी1, इलैक्ट्रानिक एस्टेट, होसुर-635109

याचिका में रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा उत्पादित मात्राओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं -

	(क) प्रभावित रेशम उत्पादक राज्य	मात्रा (मी० टन)	
		2000-01	2001-02
1.	कर्नाटक	4100	3491
2.	तमिलनाडु	355	262

3.	आंध्र प्रदेश	2091	1910
	उप-जोड़(क)	6546	5663
	(ख) अन्य रेशम उत्पादक राज्य		
1.	पश्चिम बंगाल	526	563
2.	जम्मू व कश्मीर	49	39
3.	गैर-परम्परागत राज्य	95	74
	कुल (क) और (ख)	7216	6339

जांच की अवधि के दौरान सदस्यों की संख्या, रीलिंग बेसिनों की संख्या तथा कुल कच्चे रेशम के इकाईवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

	एसोसिएशन का नाम तथा पता	सदस्यों/ इकाइयों की सं०	रीलिंग बेसिनों की सं०		कच्चे रेशम का उत्पाद (मी० टन)
			कोटेज	मल्टीएंड	
1.	ऑल सिल्क रीलर्स एसोसिएशन ककून मार्किट के पास, कोलार- 56310	360	1900	300	484
2.	कोलार सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, कोलार	80	580	100	153
3.	रामनगरम सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, रामनगरम	1460	9300	---	1784
4.	कर्नाटक स्टेट मल्टी एंड सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, रामनगरम	43	---	410	75

5.	दि प्रोग्रेसिव सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, सिदलाघट्टा	860	5218	210	994
6.	तमिलनाडु स्टेट मल्टीएंड रीलर्स एसोसिएशन, धरमपुरी	15	---	136	34
7.	दी पालाकोड सिल्क रीलर्स एसोसिएशन, पालाकोड	57	340	---	84
8.	कोयमबतूर डिस्ट्रिक्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कोयमबतूर	95	568	---	142
9.	आंध्रप्रदेश • आंध्र प्रदेश का कोई एसोसिएशन नहीं है ।	1176	6920	840	1912
	कुल	4145	24826	1996	5663

याचिकाकर्ता का देश में सम्बद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 89.33 % हिस्सा बनता है और इसलिए वह वर्तमान याचिका दायर करने की स्थिति में है ।

इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता " घरेलू उद्योग " बनता है और ये नियमों के अंतर्गत वर्तमान याचिका दायर करने की अपेक्षित स्थिति में हैं ।

ड. अन्य मुद्दे:

I. दिनांक 4 दिसम्बर, 2002 को निर्दिष्ट प्राधिकारी की अध्यक्षता में एक सुनवाई की गई थी जिसमें घरेलू उद्योग, चीन के निर्यातकों तथा चीन के दूतावास के लिए काउन्सेल (वाणिज्यिक काउन्सेलर कार्यालय) उपस्थित हुए थे । चीन के निर्यातकों के उत्तर में मूलभूत कमियों को इंगित किया गया था । अपने लिखित अनुरोधों में उन्होंने कोई कारण व प्रमाण दिए बिना चेंगडू टियानयू सिल्क कंपनी लि० द्वारा उपलब्ध की गई उत्पादन लागत संशोधित कर दी है । चूंकि ये प्रतिवादी व्यापारी हैं इसलिए उन्होंने समर्थनकारी दस्तावेजी साक्ष्य तथा दावा किए गए समायोजनों के ब्यौरे

दिए बिना अपनी औसत घरेलू खरीद कीमत तथा निर्यातों की औसत कारखाना कीमत उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्रियों से संबंधित सौदेवार आंकड़े संबद्ध वस्तु के केवल उन्हीं विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिन्होंने ऐसे व्यापारियों और अन्य को चीन के घरेलू बाजार में उक्त उत्पाद की बिक्री की है।

II. 3 मार्च, 2003 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में और इससे पहले आयातकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार:

प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी आयातक ने आयातकों की प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

(क) शाह सिल्क एंड फैब्रिक्स प्रा० लि०

1. यह जांच भेदभाव पूर्ण ढंग से की गई है जिसके द्वारा जब एक अच्छी गुणवत्ता के सिल्क धागे का जब आयात किया जाता है, पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है जबकि सस्ती गुणवत्ता के उत्पाद (ग्रेड 2ए और उससे कम) पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। ग्रेड 2 ए के लिए लागत अंतर 665/-रु० प्रति किग्रा० से अधिक है।
2. कोकून के घरेलू उत्पादक अल्पकालिक किसान हैं जो अपना उत्पाद बिक्री के लिए विभिन्न केन्द्रों तक ले जाते हैं जहां निजी क्षेत्र के और राजनैतिक नियंत्रण वाले रीलर्स अपने उत्पाद की बिक्री मनमानी कीमत पर करते हैं।
3. यदि भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतें हमारी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को कायम रखने के लिए पर्याप्त हों तो क्यों भारतीय वीवर्स अपनी जरूरतों के लिए चीन अथवा अन्य देशों में जाएं। विश्व भर में अपनाई जा रही रीलिंग प्रौद्योगिकी अभी भी भारत में अपनाई नहीं गई है। अच्छे कोकून और अच्छी रीलिंग से एक अच्छा उत्पाद बनता है। यह सत्य है कि 10 वर्षों से केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने अच्छी उपज के साथ कोकून की बाईबोल्टाइन किस्में विकसित की हैं। भारतीय सिल्क की लागत अधिक है क्योंकि हम अब भी पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे आज भी केवल 2ए ग्रेड और उससे कम की क्वालिटी का उत्पादन करते हैं। आम तौर पर भारतीय सिल्क का उपयोग केवल डुपियन फैब्रिक्स बनाने के लिए ताना (वार्प) धागे के रूप में किया जा रहा है। चीनी, ब्राजीलियन और अन्य मूल के कच्चे रेशम की उपलब्धता के बावजूद भारतीय वीवर्स अच्छी गुणवत्ता की फैब्रिक्स की बुनाई

कर रहे हैं और विभिन्न देशों को निर्यात कर रहे हैं और इस प्रकार वे चीनी फैब्रिक निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ।

4. पाटनरोधी प्रस्तावों के कारण मूल्यवर्द्धित भारतीय सिल्क निर्यात निश्चित रूप से प्रभावित होगा । यदि वीवर्स को इन साड़ियों की बुनाई ऊंची लागत के धागों से करनी पड़े तो इसका परिणामी प्रभाव यह होगा कि महिला साड़ियों की लागत भी बढ़ जाएगी ।

5. पाटनरोधी शुल्कों से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भारत में असंगठित क्षेत्र में वीवर्स की कमी हो जाएगी और यह सबके हित में नहीं होगा ।

6. पाटनरोधी शुल्कों से तरकरी को बढ़ावा मिलेगा ।

(ख) द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल:

हम किसानों की रीरिंग सिल्क के विरुद्ध नहीं हैं, उन्हें सस्ते आयातों से संरक्षण की आवश्यकता है । इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है यदि सस्ते आयात रेशम उद्योग को प्रभावित करते हैं तो हम इस शुल्क को लगाने का विरोध नहीं कर रहे हैं । यह अभ्यावेदन आवश्यक हो गया है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क की दर असामान्य स्तर पर निर्धारित की गई है, जो वास्तव में सिल्क वीविंग उद्योग और बाद में निर्यात के विनाश को बढ़ावा देगी । वास्तव में हमने स्थानीय रेशम उद्योग के बचाव के लिए मलबरी कच्चे रेशम पर सीमाशुल्क में 5 % से 10 % की वृद्धि की उम्मीद की । लेकिन इस असामान्य बढ़ोतरी ने उत्पादन प्रक्रिया पर रोक लगाई है । हम समझते हैं कि समस्त पावरलूम सिल्क वीविंग उद्योग- कर्नाटक में 50,000, जो घरेलू बाजार और रेशम व्यापारी निर्यातकों को सिल्क फैब्रिक्स की आपूर्ति करता है, पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जिससे बेरोजगारी की समस्या पैदा होने जा रही है । कर्नाटक के अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सिल्क पावरलूम वीविंग उद्योगों द्वारा इस अधिसूचना के प्रभाव को उत्तरोत्तर महसूस किया जा रहा है और उनकी बर्बादी आसन्नवर्ती है ।

भारतीय उत्पादक लगभग 15,000 टन मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं । इसका अधिकांश भाग ग्रेड रहित होता है और जिसकी गुणवत्ता ऐसी होती है जिसका उपयोग घरेलू एवं निर्यात बाजार दोनों के लिए पावरलूमों पर फैब्रिक के उत्पादन हेतु किया जा सके । भारतीय कच्चे रेशम से निर्मित यार्न का उपयोग केवल हैंडलूम पर किया जा सकता है । मलबरी कच्चे रेशम के

15,000 टन के उत्पादन की तुलना में हमारी मांग 25,000 टन वार्षिक है, जो 10,000 टन कम है जिसके लिए आयात अपेक्षित है। यदि आयातित कच्चे रेशम की कीमत काफी अधिक रहती है तो यह आयातों के लिए निवारक के रूप में कार्य करेंगी। किंतु स्थानीय घरेलू उद्योग असामाजिक तत्वों द्वारा तस्करी से लाए गए मलबरी कच्चे रेशम से पट जाएगा इससे राजस्व की हानि होगी। पाटनरोधी दर के रूप में 33.19 अमरीकी डालर पर निर्धारित की गई आयात कीमत पूर्णतः मनमानी और औचित्यरहित है क्योंकि इस कीमत पर विश्व में कहीं पर भी 3ए और उससे अधिक की गुणवत्ता वाले एमआरएस की बिक्री भी नहीं की जाती है।

(ग) वाराणसी वस्त्र उद्योग संघ

1. घरेलू यार्न की कीमत में मांग के अभाव में कमी आई है क्योंकि चीन से सिल्क फैब्रिक का आयात इतनी सस्ती दरों पर हुआ है जो हमारी उत्पादन लागत से भी कम है। इसी वजह से घरेलू यार्न का उत्पादन भी घटा है। चीन से सस्ते सिल्क फैब्रिक के आयात के कारण अंतिम स्टॉक में भी वृद्धि हुई है। चीनी सिल्क यार्न (बिना बटा हुआ) के आयात में निर्यात बाजार तथा बिना बटा हुआ (अन-टिविस्टिड) गुणवत्ता के आयातित कच्चे रेशम यार्न द्वारा विनिर्मित फैब्रिक्स संबंधी पावरलूम उद्योग में मांग अधिक होने के कारण वृद्धि हुई है।
2. जहां कच्चे रेशम के आयात की अनुमति 30.10.1998 को एसआईएल के तहत की गई थी वहीं 2ए ग्रेड से कम के कच्चे रेशम के आयात को प्रतिबंधित सूची में ही रखा गया था। ऐसा इस वजह से किया गया था क्योंकि 2ए और उससे उच्च ग्रेड के यार्न का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है और इस प्रकार आयात किए जाने वाले 2ए और उससे उच्च ग्रेड का घरेलू यार्न प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है। द्वितीयतः " बिना बटे गए " भारत में उत्पादित यार्न का उपयोग टिविस्टिंग के बाद ही किया जा सकता है। इसका उपयोग चीनी यार्न की तरह " न बटी गई स्थिति में " नहीं किया जा सकता। भारत में निर्यात एवं पावरलूम फैब्रिक का निर्माण केवल " न बटी गई " (अन-टिविस्टिड) गुणवत्ता में ही किया जाता है।
3. पाटनरोधी शुल्क लगाने से कीमत में 80 % से अधिक की वृद्धि हो जाएगी जो कि एक भारी वृद्धि है। 2 ए यार्न का आयात 13-14 डालर के बीजक मूल्य पर किया जाता है जो

35 % सीमाशुल्क जोड़ने के बाद 19 डालर बनता है । इसे बढ़ाकर 33.19 कर दिया गया है । पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद बाजार में अब कीमत 950 रु० प्रति किग्रा० के बजाय बढ़कर 1700 रु० प्रति किग्रा० हो जाएगी । पाटनरोधी शुल्क की घोषणा के बाद ही बाजार कीमत में 250 रु० तक की वृद्धि हो चुकी है ।

4. घरेलू सिल्क यार्न के उत्पादन और उसकी खपत में कमी आई है जिसकी वजह चीनी सिल्क यार्न का आयात नहीं है जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है । इसमें चीन से कम कीमत पर सिल्क फैब्रिक के आयात के कारण कमी आई है । अतः भारतीय विनिर्माता आयातित सिल्क फैब्रिक, जो घटिया गुणवत्ता का भी है, के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमारी लागत आयातित सिल्क फैब्रिक लागत के बराबर है । उदाहरणार्थ 60 ग्रा० आयातित क्रैप सिल्क की वर्तमान बुकिंग 1.40 डालर है जो 30 % सीमाशुल्क जोड़ने के बाद 90 रु० प्रति मी० टन बनती है जो घरेलू यार्न का उपयोग करके हमारे द्वारा निर्मित सिल्क फैब्रिक की लागत के बराबर है । यदि सिल्क फैब्रिक का कोई विनिर्माण नहीं किया जाएगा तो रेशम उद्योग का विकास कैसे होगा ? यदि हम आयातित चीनी रॉ सिल्क यार्न से सिल्क फैब्रिक (क्रैप 60 ग्रा० गुणवत्ता) का विनिर्माण करते हैं तो पाटनरोधी शुल्क के बाद आयातित तैयार चीनी सिल्क फैब्रिक की 92 रु० की लागत की तुलना में केवल कच्ची सामग्री की लागत 236 रु० बनेगी ।

5. वाराणसी और उत्तरप्रदेश का समूचा क्षेत्र बनारसी फैब्रिक के उत्पादन पर निर्भर है जिसमें 5 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिला हुआ है । यह गामीण कुटीर उद्योग है। यह पूर्णतः स्वः वित्त पोषित उद्योग है जिसे निर्यात हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है । निर्यात किए जाने वाले 75 % से अधिक सिल्क का विनिर्माण वाराणसी में होता है । आयातित चीनी सिल्क यार्न के 50 % की खपत केवल वाराणसी में की जाती है । शेष भारत में केवल 50 % की खपत होती है । पाटनरोधी शुल्क के कारण वाराणसी में हैंडलूम और पावरलूम, दोनों उद्योग प्रभावित होंगे । यहां यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उत्पादन के 90 % की खपत केवल कर्नाटक द्वारा की जाती है ।

(घ) कर्नाटक स्टेट वीवर्स सेंट्रल कमेटी; मै. मैसूर पावरलूम सिल्क मैन्यूफैक्चरर्स को आपरेटिव सोसाइटी लि०, मै. चामुण्डी टेक्सटाइल (सिल्क मिल्स लि०); बेंगलूर डिस्ट्रिक्ट एंड बेंगलूर रूरल डिस्ट्रिक्ट पावर लूम वीवर्स प्रोडक्शन एंड सेल्स को आपरेटिव फेडरेशन लि०

1. प्राधिकारी ने भारतीय शहतूती कच्चे रेशम पर समान वस्तु के रूप में किसी ग्रेड का संदर्भ लिए बिना विचार किया है। यह सुविदित तथ्य है कि भारत में श्रेणीकरण की कोई प्रणाली नहीं है। चीन और भारत के रेशम की गुणवत्ता में अनेक प्रकार के अंतर हैं और जिनकी विधिवत जानकारी है। अधिकांश भारतीय उत्पादन मल्टी वोल्टाइन किस्म का होता है जबकि चीन का उत्पादन बाई वोल्टाइन किस्म का होता है। भारतीय रेशम का उपयोग धागे के बार बार टूटने के कारण जब पावरलूम में किया जाता है तो उसकी उत्पादकता में काफी गिरावट आ जाती है। इस प्रकार से बार बार टूटने की घटना चीन के धागे की तुलना में भारतीय धागे में सांद्रणता एवं क्षमता में कमी के कारण घटित होती है।
2. यह सुविदित तथ्य है कि भारतीय घरेलू उद्योग ने ग्रेड 2 ए के बराबर और उससे अधिक के ग्रेड के कच्चे रेशम का कभी विनिर्माण नहीं किया है। विगत में केवल 2ए ग्रेड से कम के कच्चे रेशम का आयात प्रतिबंधित था और 2ए तथा उससे ऊपर के ग्रेड के आयात की अनुमति मुक्त रूप से प्रदान की जाती थी।
3. चीन से आयातित शहतूती कच्चे रेशम का उपयोग मुख्यतः पावरलूमों में किया जाता है जबकि भारतीय रेशम का उपयोग मुख्यतः हैण्डलूमों में किया जाता है। चीन के कच्चे रेशम का उपयोग सुविख्यात भारतीय सिल्क साड़ियों के विनिर्माण में कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि चीनी रेशम में चमक और साइजिंग का अभाव होता है। चीनी सिल्क का उपयोग आरगेंजा के विनिर्माण में किया जाता है तथा भारतीय रेशम का उपयोग आरगेंजा के विनिर्माण में नहीं किया जाता है।
4. जहां तक क्षति का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि कुल उत्पादन 6546 मी. टन से घट कर 1566 मी. टन हो गया है। यह कृषि से संबंधित उत्पाद है। ककूनों का उत्पादन शहतूत के पौधों के उत्पादन से घनिष्ठतः संबद्ध होता है। इस पहलू की कोई जांच नहीं की गई है।
5. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अधिकांश संयंत्र 60% क्षमता पर चल रहे थे और उनमें से कुछ संयंत्र बंद हो गए हैं। इस संबंध में आवेदन के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह दावा आधारहीन है।
6. उन्होंने वस्तुसूची बिक्री लागत, लाभ, हानि, निवेश, निवल मूल्य, रोजगार आदि के बारे में कोई ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मांग में कोई अंतर नहीं है।
7. प्राधिकारी ने 33.19 अमरीका डालर/किग्रा का एक संदर्भ मूल्य निर्धारित किया है जो न केवल मनमाना है बल्कि बहुत अधिक भी है।

8. यहां 6 से 8 लाख पावरलूम वीवर्स हैं जिनकी आजीविका खतरे में है। घरेलू उद्योग ने उन्हें कभी कच्चे रेशम की अपेक्षित मात्रा एवं गुणवत्ता की आपूर्ति नहीं की। घरेलू उद्योग द्वारा मुख्यतः हैण्डलूम वीवर्स को आपूर्ति की जाती है। पावरलूम वीवर्स उनका बाजार नहीं थे। इस मामले में, यदि शुल्क को कम नहीं किया जा सकता तो कम से कम पावरलूमों में उपयोग के प्रयोजनार्थ आयातित वस्तु के शुल्क से छूट प्रदान की जाए। किसी भी स्थिति में संदर्भ कीमत को यथार्थ स्तर तक नीचे लाए जाने की आवश्यकता है।

प्रत्युत्तर

1. हम अपने निवेदन को दोहराते हैं कि भारतीय घरेलू उद्योग ने ग्रेड 2ए के बराबर एवं उससे अधिक के ग्रेड के कच्चे रेशम का कभी विनिर्माण नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा बाई वोल्टाइन किस्म का उत्पादन बहुत निम्न तथा वाणिज्यिक रूप से नगण्य था। यह एक अविवादित तथ्य है कि अंतिम रूप से विभिन्न उपयोगों सहित चीनी कच्चा रेशम तथा भारतीय रेशम पूरी तरह से दो भिन्न उत्पाद हैं।

2. याचिकाकर्ता ने घरेलू उत्पादन, बिक्रियों आदि से संबंधित वृहद स्तर पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं इससे अलावा याचिकाकर्ता को अलग अलग इकाई-वार आंकड़े और सभी याचिकाकर्ताओं का एक समेकित आंकड़े उपलब्ध कराना चाहिए था।

(ड.) सिल्क ट्रेड एसोसिएशन (रजि.), वाराणसी

1. वाराणसी में पावरलूम तथा हैण्डलूम उद्योग में कच्चे सिल्क को नॉट थ्रोन (अनटविस्टेड) स्थिति में उपयोग किया जाता है जिसके लिए चीनी गुणवत्ता अच्छी सिद्ध होती है चूंकि घरेलू कच्चे रेशम की गुणवत्ता इसके लिए उपयुक्त नहीं है।

2. भारत में उत्पादित कच्चे रेशम (नॉट थ्रोन) का सामान्यतः उपयोग बटाई के बाद होता है। यह न तो संभव और न ही व्यवहार्य है कि इसे चीनी कच्चे रेशम की तरह नॉट थ्रोन स्थिति में उपयोग किया जाए।

3. अच्छी गुणवत्ता वाले नियमित चीनी कच्चे रेशम की मांग के कारण बहुत से पावरलूम तथा हैण्डलूम पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। चीनी रेशम फैब्रिक्स के आयात के कारण पहले ही बहुत से लूम, जो रेशम फैब्रिक्स (क्रेप 60 ग्राम गुणवत्ता) का उत्पादन करते थे, बंद पड़े हुए हैं।

4. चीनी कच्चे रेशम का इस समय मूल्य लगभग 13-14 अमरीकी डालर/किग्रा है। 20 अमरीकी डालर/किग्रा से ऊपर का यह अत्यधिक आयात शुल्क तस्करों के लिए पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध कराएगा और तस्करों पुनः प्रारंभ हो जाएगी जो न तो व्यापार के और न ही सरकार के हित में है।

5. इस प्रकार से आयात किया गया यार्न घटिया गुणवत्ता का होगा, आपूर्ति अनियमित हो जाएगी तथा कीमतों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आ जाएगा। इससे कीमतों का आकलन कठिन हो जाएगा तथा सिल्क फैब्रिक्स साड़ियों एवं मेड अप्स के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यात आदेशों को निष्पादित करने में व्यवधान पड़ेगा।

6. इससे घरेलू रेशम उत्पादन उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा जिसके लाभ के लिए शुल्क लगाया गया है। घरेलू रेशम उत्पादन उद्योग की वृद्धि में चीनी सिल्क यार्न नहीं बल्कि चीन से कम कीमत वाले सिल्क वस्त्रों जो अब मुक्त रूप से आयात के योग्य हैं, के आयात के कारण बाधा पहुंची है। कच्चे रेशम की घरेलू गुणवत्ता का उपयोग मुख्यतः इन फैब्रिक्स में किया जाता था और चूंकि यह अब भारत में मुक्त रूप से आयात योग्य है और उच्चतर गुणवत्ता का है तथा इसकी कीमत कम है, इसलिए भारत में इन फैब्रिक्स के उत्पादन में व्यवधान आया है चूंकि रेशम फैब्रिक्स का विनिर्माण जो घरेलू रेशम यार्न का उपयोग करके किया जाता था, उसमें अब कमी आई है और इसलिए इससे देश में रेशम उद्योग के विकास में बाधा पहुंची है और आयातित कच्चे रेशम से इसके विकास में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ है।

च. प्योर सिल्क वीवर्स एसोसिएशन

1. हम एक शीर्षस्थ संगठन हैं जिनमें प्योर सिल्क यार्न टि्वस्टर, सिल्क फैब्रिक वीवर डायर, स्थानीय वीवर एसोसिएशन तथा सिल्क को-ऑपरेटिव सोसाइटियां शामिल हैं जिनके द्वारा 5000 से अधिक पावरलूमों की जरूरत को पूरा किया जाता है। हममें से अधिकांश सदस्य घरेलू बाजार और रेशम निर्यातकों को रेशम फैब्रिक की आपूर्ति करते हैं।

2. आरंभ में हम इस मुद्दे को अत्यधिक स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसानों द्वारा रेशम की खेती किए जाने के विरुद्ध नहीं हैं, सस्ते आयातों से उनकी रक्षा करने की जरूरत है। अतः हम सुस्पष्ट तौर पर इस शुल्क को उस स्थिति में लगाए जाने के खिलाफ नहीं हैं यदि सस्ते आयात से रेशम उद्योग प्रभावित होता है। यह ज्ञापन उस स्थिति में आवश्यक हो गया है जब शुल्क की दर असामान्य स्तर पर निर्धारित की गई है जिससे वस्तुतः रेशम बुनाई उद्योग नष्ट हो जाएगा।

3. इस असामान्य वृद्धि से उत्पादन प्रक्रिया बाधित हुई है। समूचा पावरलूम सिल्क वीविंग उद्योग-कर्नाटक में 50,000 और गुजरात में 5,000 लूम तथा पश्चिम बंगाल तथा बिहार आदि में लगभग 25,000 लूम जिनसे रेशम फैब्रिक की आपूर्तियां घरेलू बाजार और रेशम व्यापारी निर्यातकों को की जाती हैं, के प्रचालन में रूकावट आ गई है जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने जा रही है। कर्नाटक के अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में सिल्क पावर लूम वीविंग उद्योग इस अधिसूचना के प्रभाव को उत्तरोत्तर महसूस कर रहे हैं और उनका विनाश आसन्नवर्ती है।

छ. फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री

1. स्वदेशी कीमतों में गिरावट आर एंड टी के परिणामस्वरूप उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि के कारण आई है न कि कम कीमत के कारण।

2. देश में उत्पादित 16,000 टन रेशम की कुल मात्रा की तुलना में वर्तमान घरेलू मांग 23,000 टन की है जिससे मांग और आपूर्ति में 7,000 मी.टन का भारी अंतर उत्पन्न हो जाता है।

3. शहतूती कच्चे रेशम की मांग- आपूर्ति में यह अंतर पावरलूमों के लिए मुख्यतः वार्प ग्रेड के रेशम के संबंध में विद्यमान है। पावरलूमों द्वारा तरजीह शुदा वार्प ग्रेड का रेशम सामान्यतः केवल बाई वोल्टाइन प्रजातियों से प्राप्त होता है जिसकी पूर्ति चीनी बाई वोल्टाइन रेशम के आयात द्वारा की जा रही है।

4. देश में ऐसे 30,000 से अधिक पावरलूम और 1,80,000 से अधिक हैंडलूम हैं जो फैब्रिक के विनिर्माण हेतु प्योर सिल्क यार्न का उपयोग कर रहे हैं। प्योर सिल्क फैब्रिक के उत्पादन में 6 हैंडलूम एक पावरलूम के बराबर होता है। दोनों क्षेत्रों का उत्पादन लगभग समान है। दोनों क्षेत्रों में 1 मिलियन से अधिक कामगार नियोजित हैं। पाटन रोधी शुल्क के कारण ये पावरलूम उत्पादन बंद कर देंगे और कामगार बेरोजगार हो जाएंगे।

III. दिनांक 3 मार्च 2003 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में निर्यातकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार:-

चीन के प्रत्येक निर्यातक के विचारों को प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 4(क) से 4(ख) में विस्तार से दर्ज किया गया है। चीन के निर्यातकों ने अपने लिखित अनुरोध 27 मई 2003 को दायर किए थे और उन्होंने चीन में सार्स के फैलने के कारण हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया था;

1. आरंभ में सिल्क यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना उपयोगी होगा। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों का उपभोग करते हैं और प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया द्वारा ककूनों का उत्पादन करते हैं। रेशम पालक ककूनों को चुनते हैं जिन्हें वे बाजार में सिल्क रीलरों को बेच देते हैं। सिल्क रीलर बाद में उन ककूनों से यार्न बनाते हैं। यार्न के निर्माण से संबंधित लागत निम्नानुसार है:-

1किग्रा सिल्क यार्न प्राप्त करने के लिए 6.5 किग्रा ताजे ककूनों की जरूरत होती है, इस प्रकार 125 रु०/किग्रा की दर से 6.5 किग्रा ताजे ककूनों की लागत

810 रूपए

रीलिंग लागत

340 रूपए

कुल

1,150 रूपए

घटाएं- सह उत्पादों/अवशिष्ट की बिक्री से प्राप्त आय

350 रूपए

शेष अनामेलित लागत

800 रूपए

1किग्रा सिल्क यार्न की बिक्री कीमत

1000 रूपए

सिल्क रीलर को लाभ

200 रूपए

उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलेगा कि सिल्क रीलरों की लागत के अधिकांश भाग में ककून की लागत शामिल होती है। सिल्क रीलरों द्वारा प्रत्यक्ष लागत की पूर्ति सह-उत्पाद/अवशिष्ट की बिक्री में से की जाती है और उसके बाद सिल्क रीलर 200 रूपए/किग्रा का मुनाफा कमाते हैं।

अनुरोध है कि ककून एक विनिर्मित उत्पाद नहीं है, इसका विकास प्राकृतिक रूप से होता है। अतः सिल्क रीलर ककून को सिल्क यार्न में बदलने के लिए केवल उजरती कार्य का निष्पादन और मूल्यवर्द्धन सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाएगा कि ककून को सिल्क यार्न में परिवर्तित करते समय ककून की भौतिक विशेषताओं में मात्र परिवर्तन होता है जबकि उत्पाद की रासायनिक संरचना समान बनी रहती है। अनुरोध है कि भौतिक परिवर्तन मात्र से वस्तु का विनिर्माण हो जाता है। इस संबंध में सी एस टी (डी वाई) बनाम पायो फूड पैकर्स 1980 सप एस सी सी 174 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जा सकता है, अतः अनुरोध है कि सिल्क यार्न जो कि मूलतः और अनिवार्यतः एक प्राकृतिक उत्पाद है, न कि विनिर्मित उत्पाद, को वर्तमान पाटनरोधी कार्रवाइयों का आधार नहीं बनाया जा सकता।

आगे यह निवेदन किया गया है कि केवल यह तथ्य कि सिल्क रीलर अपनी कीमत पर 17% से अधिक का लाभ कमा रहे हैं, इस बात का संकेतक है कि सिल्क रीलरों को कोई क्षति नहीं हो रही है, जिसे इन जाँचों का आधार बनाया जा सकता है।

चीनी रेशम गुणात्मक रूप में घरेलू रूप से उत्पादित रेशम से भिन्न है। चीनी रेशम सूखे ककून से बनाया जाता है जबकि भारतीय रेशम ताजे ककून से निर्मित होता है। चीनी निर्यातकों द्वारा अपनाई गई तकनीक, घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई तकनीक से कहीं अधिक उत्कृष्ट है, जिसके परिणामस्वरूप रेशम के यार्न की गुणवत्ता में काफी अंतर होता है, जहाँ भारतीय सिल्क का प्रयोग केवल हैंडलूम उद्योग में किया जा सकता है वहीं चीनी सिल्क यार्न, पावरलूम पर बुनाई के लिए उपयुक्त है। आयातकों की यह शिकायत रही है कि पावरलूम में भारतीय सिल्क यार्न का उपयोग करने पर यार्न अक्सर टूट जाता है।

निवेदन किया गया है कि भारत में कच्चे सिल्क की मांग 25,000 मी०टन है, जिसमें से 15,000 मी०टन की पूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा होती है, परिणामतः 10,000 मी०टन की होने वाली कमी की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती है।

Iv(क) 3 मार्च 2003 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचार

1. हम निर्दिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 20 दिसंबर, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों में दिए गए तथ्यों को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। तथापि, हम इस आशय का अतिरिक्त निवेदन करना चाहेंगे कि, " चीन जनवादी गणराज्य के सभी निर्यातकों और आयातकों को अथवा जो चीन जनवादी गणराज्य से वस्तु प्राप्त करते हैं, को 15.07.1999 और 31.05.2001 को यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 पैराग्राफ 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालनकर्ताओं के रूप में माना जाना चाहिए।"

2. घरेलू उद्योग दोहराना चाहेगा कि चीनी मलबरी कच्चे रेशम के निरंतर पाटन से गंभीर वास्तविक क्षति हुई है तथा इससे शोध में प्राप्त हुई उल्लेखनीय उपलब्धि प्रभावहीन हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप रीलर कर्ज का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने घरेलू उद्योग में भारी निवेश किए हैं।

3. आयातों की मात्रा

(क) 2000-2001 में आयातों की मात्रा की तुलना में जांच की अवधि के दौरान चीन ज०ग० से मलबरी कच्चे सिल्क के कुल आयातों में 60.57% की वृद्धि हुई थी।

(ख) कुल आयातों में चीन ज०ग० का हिस्सा 2000-2001 में 91.68% तथा 2001-2002 में 93.93% था (12 महीने-आई)

4. याचिकाकर्ताओं के तर्क:-

(i) जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का आसन्न खतरा है।

(iii) उद्योग की स्थिति का मूल संकेतक लाभप्रदता है, जो लगातार गिरावट की ओर है और वर्तमान में हानि में परिवर्तित हो गई है। यह संबद्ध देशों से वस्तुओं की औसत कीमत के कारण हो रही है, जो 2000-2001 से लगातार गिरावट की ओर है तथा अब अत्यंत नीचे गिर गई है जिसके परिणामस्वरूप मात्रा में वृद्धि हो रही है।

(iv) बाजार केवल एक है जिसमें पाटित चीनी आयात, भारतीय मिलों के उत्पादों से बराबरी की प्रतिस्पर्धा करते हैं। पूर्तिकर्ता के चुनाव का निर्धारण, कीमतों के आधार पर होता है।

(v) बराबर की प्रतिस्पर्धा तथा संबद्ध वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के एक विस्तृत क्षेत्र के मध्य प्रतिस्पर्धा से पूर्व अर्थमितीय जांच से पता चलता है कि आयात तथा घरेलू उत्पाद अत्यधिक प्रतिस्थापनीय है।

5. बिक्री तथा बाजार हिस्सा:-

(i) पिछले वर्ष की तुलना में याचिकाकर्ता की बिक्री 48.09% तक गिर गई है।

(ii) पिछले वर्ष के बाजार की तुलना में कुल घरेलू बिक्री 44% (अनुमानतः) (43.54%) तथा घरेलू उद्योग की बिक्री 48% तक घट गई है।

(iii) पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग का हिस्सा 62% से 35% तक अर्थात् 27% के लगभग गिर गया है।

(iv) पिछले वर्ष की तुलना में पाटित आयातों का बाजार हिस्सा 30% से 54% तक बढ़ गया है।

(v) पिछले वर्ष की तुलना में समग्र माँग में पाटित आयातों के बाजार हिस्से में 32% से 57% तक की वृद्धि हुई है।

(vi) भारत में संबद्ध वस्तु की कुल खपत की तुलना में पाटित आयातों की मात्रा तथा बाजार हिस्सा, एक वर्ष की तुलना में दोगुना हो गया है और अब संबद्ध देशों से और भी कम कीमतों पर आयातों की मात्रा में वृद्धि हो रही है:

(क) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लाभ प्रदता की कीमत पर वृद्धि हुई है।

(ख) कुल बिक्री, खपत तथा उत्पादन की तुलना में पाटित आयातों में संपूर्ण अर्थों में वृद्धि हुई है।

(ग) संबद्ध देशों से जांच अवधि के बाद भी आयातों में वृद्धि हो रही है जिससे घरेलू उद्योग के लिए क्षति (पहले से ही क्षतिग्रस्त) का खतरा उत्पन्न हो रहा है।

6. कीमत पर पाटित आयातों का प्रभाव:

(क) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की औसत कीमतें 40% तक गिर गई हैं तथा उनमें गिरावट जारी है। घरेलू उत्पादकों के पास एक ही उपाय है - या तो वे कीमतें घटाएं या अपना बाजार हिस्सा गंवाएं। घरेलू उत्पादकों के पास अपने क्षमता उपयोग को क्षतिकारक स्तर तक गिरने से बचाने के लिए पहले उपाय को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था।

(ख) औसत घरेलू निबल बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई है।

(ii) जिस अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन की औसत लागत में वृद्धि हुई है, उसी अवधि में निवल बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई है।

(iii) आयातित वस्तु की कम कीमत को पूरा करने के लिए ग्राहक की अपेक्षा के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्त में भारी गिरावट आई है, उद्योग अब घाटे में चल रहा है अर्थात् यह उत्पादन की कुल लागत को प्राप्त करने में भी असमर्थ है।

इसके अलावा पाटित आयातों के बाजार ने बाजार कीमत में भारी कमी की है। वस्तु सूची में हुई वर्तमान वृद्धि से यह पता चलता है कि यदि संबद्ध आयातों में आगे और वृद्धि नहीं होती है तो भी कीमतों में भारतीय उत्पादकों के लिए उनमें स्थिरता आने से पूर्व आगे और गिरावट आएगी। किंतु संबद्ध आयातों की मात्रा बढ़ने के कारण कीमतें स्थिर नहीं हो सकती और इनमें आगे और गिरावट आती रहेगी तथा अधोगामी रूख बना रहेगा। यह संबद्ध देशों से उक्त वस्तु की कीमतों में गिरावट से निष्कर्षित सिद्ध हो गया है।

(ग) कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू उत्पादकों को इस अवधि के दौरान लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा था।

भारतीय उत्पादकों को कीमत में भारी कमी करनी पड़ रही है। उन्हें उस समय कीमत में गिरावट करनी पड़ रही है जब प्रत्येक स्वदेशी उत्पादक की लागत बढ़ रही है। यह केवल कीमत ह्रास नहीं है बल्कि कीमत में अत्यधिक न्यूनीकरण है।

7. संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की औसत सीआई एफ कीमत में तेजी से गिरावट आने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है जिसकी वजह से,

(क) अत्यधिक कम कीमत पर घरेलू बाजार में संबद्ध आयातित पाटित उत्पादों की बिक्री के कारण घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से और स्वदेशी बिक्री का नुकसान हुआ है।

(ख) कीमत ह्रास से "कीमत वृद्धि" से वंचित होना पड़ा है जिससे घरेलू उद्योग को अन्ततोगत्वा कम बिक्री प्राप्त हुई है।

(ग) घरेलू उद्योग ने क्षमता का कम उपयोग किया है।

8. लाभप्रदता पर प्रभाव

(क) निवल बिक्री प्राप्ति में गिरावट आई है,

(ख) उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है जिसे ग्राहकों पर नहीं डाला जा सकता।

(ग) मात्रा में वृद्धि के साथ साथ संबद्ध देशों से उक्त वस्तु की सी आई एफ कीमतों में कमी तथा घरेलू बिक्री कीमत में परिणामी गिरावट और उत्पादन लागत में वृद्धि परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता क्षीण हुई है और वह बंद होने की स्थिति में है,

(घ) उपर्युक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि पाटित आयातों और उनकी कम कीमत के परिणामस्वरूप लाभप्रदता क्षीण हुई है और घरेलू उद्योग के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हुआ है।

9. उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

(क) जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में लगभग 14%(13.48%) तक की गिरावट आई है।

(ख) क्षमता उपयोग में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 30% तक की गिरावट आई है।

10. अंतिम स्टॉक

पिछले वर्ष की तुलना में अंतिम स्टॉक में लगभग 300% की वृद्धि हुई है।

11. सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि चीन में अधिकांश बिक्री सौदे सरकारी कंपनियों के बीच होते हैं। कच्चे रेशम का उत्पादन मुख्यतः सरकारी यूनिटों द्वारा ही किया जाता है। माननीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे की जांच यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा (7) और (8) को ध्यान में रखते हुए उचित ढंग से की है।

प्राधिकारी ने नोट किया है कि चीन की कंपनियों द्वारा उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्री से संबंधित प्रश्नावली की संगत परिशिष्टों में सूचना प्रस्तुत नहीं की है। न ही उन्होंने पैरा (8) के उपपैरा (3) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खंडन करने के मानदंड के बारे में कोई सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि चूंकि उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्री के बारे में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं इस लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के उप-नियम 2(1) और (ii) के साथ पठित धारा 9क(1)(ग)(1) और (ii) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता और वे यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 3 के पैराग्राफ 8 में निहित इस परीक्षण पर खरी उतरने में विफल रही हैं कि उन्हें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के विनिर्माता अथवा निर्यातक के रूप में माना जाए। बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे/अलग अलग व्यवहार का दावा करने के लिए निर्यातक अथवा विनिर्माता को पैरा 8 अनुबंध-1 में निहित सभी मापदंडों को पूरा करना जरूरी होता है जिसके अभाव में उन्हें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालनरत माना जाएगा। पीआरसी से फौरो-मॉलिब्डेनन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के ईयू के निर्णय की एक प्रति संलग्न है।

किसी भी मामले में व्यापारी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं कर सकते और पीआरसी से ग्लायसीन के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले ईयू के निर्णय की एक प्रति संलग्न से जिसमें ईयू ने यह उल्लेख किया है कि " संबंधित कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं किए जाने के कारण तीन दावों को स्वीकार किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कम शुद्धतावाली ग्लायसीन की खरीद की थी जिस पर उन्होंने ऐसी उत्पादन प्रक्रिया निष्पादित की थी जिससे विचाराधीन उत्पाद की रासायनिक संरचना अथवा भौतिक विशेषताएं परिवर्तित नहीं हुई थीं। अतः उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के व्यापारियों की समानता की थी। चूंकि उत्पादकों द्वारा ही बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है इसलिए उनके दावों को अस्वीकार करना पड़ा था। "

12. निर्यात कीमत

हम निर्यात कीमत के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के जाँच परिणामों को स्वीकार करते हैं। कारखाना-द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा किए गए दावे के अनुसार समायोजन करने के बाद किया गया है। दावानुसार समायोजन पर विचार करने के बाद अलग-अलग निर्यातकों के लिए कारखाना-द्वार पर भारित औसत निर्यात कीमत निकाली गई है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं बाद के अनुरोध

1. आयातित एवं स्वदेश में उत्पादित समान वस्तुओं का पारस्परिक अदला बदली/वाणिज्यिक प्रतिस्थापन । यह कहना तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना है कि चीनी रेशम का उपयोग केवल बिजली करघों में किया जाता है जबकि भारतीय रेशम का उपयोग केवल हथकरघों में किया जाता है । यह कहना कि केवल चीनी रेशम आर्गेजा का उत्पादन कर सकता है, असंगत है क्योंकि देश में आर्गेज की बहुत कम मात्रा का उत्पादन किया जाता है । भारतीय मल्टीएंड सिल्क और फिलाचर सिल्क जो वार्व किस्म का है, का उपयोग देश के अनेक बिजली करघा समूहों में किया जाता है । कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (केएसयूसी) जो अपनी प्रसिद्ध " मैसूर सिल्क " का विपणन करता है, अपने बिजली करघों में भारतीय कच्चे रेशम का व्यापक उपयोग करता है । भारतीय मल्टीएण्ड रीलर्स विशेष रूप से उन अनेक निर्यातकों को भारतीय कच्चे रेशम का व्यापक उपयोग करता है । भारतीय मल्टीएण्ड रीलर्स विशेष रूप से उन अनेक निर्यातकों को भारतीय कच्चे रेशम की अपूर्ति करते हैं जो बिजली करघा फैब्रिक्स का विनिर्माण करते हैं । साथ ही प्रमुख हथकरघा समूहों जैसे हिन्दुपुर, धरमवरम (आन्ध्र प्रदेश), सलेम (तमिलनाडु), मोलाकलमुरु (कर्नाटक), में भारतीय हथकरघों ने चीनी रेशम का व्यापक उपयोग करना शुरू कर दिया है । इस प्रकार, आयातित और घरेलू दोनों रेशमी धागे वस्तुतः समान उत्पाद हैं जिनकी कीमत के आधार पर अदला-बदली की जा सकती है । पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी रेशम ने अनेक बिजली करघों और हथकरघों में भारतीय रेशम की जगह ले ली है क्योंकि चीनी कंपनियों ने अपने रेशम की कीमतें घटाकर काफी कम कर दी हैं जिससे रेशम धागे के भारतीय विनिर्माताओं के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया है ।

2. घरेलू उद्योग में बिबोल्टीन रेशम का उत्पादन: चीनी रेशम का देश में आयात इसलिए नहीं किया जा रहा है कि यह बिबोल्टीन सिल्क है बल्कि देश में मांग आपूर्ति के अंतराल की वजह से किया जा रहा है । चूंकि चीनी बिबोल्टीन सिल्क और भारतीय मल्टी-बिबोल्टीन सिल्क दोनों ही कम उपयोग एक समान उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है, इसलिए देश में चीनी कच्चे रेशम की अप्रत्याशित कम कीमतों पर आयात करने से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । हाल ही में भारत में बिबोल्टीन सिल्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्लान स्कीमों और विभिन्न परियोजनाओं में

पर्याप्त निवेश किया था। चीनी कंपनियां इसे एक खतरे के रूप में मानती हैं और उन्होंने प्रारंभिक चरण में ही भारतीय बिबोल्टाइन सिल्क के उत्पादन को नुकसान पहुंचने की दृष्टि से कम कीमतों पर रेशम के पाटन का आश्रय लिया है। भारत में चीनी रेशम का कई वर्षों से आयात किया जा रहा है। चीनी कंपनियों द्वारा पाटन किए जाने की केवल अब शिकायतें की गयी हैं। हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि चीनी कंपनियों द्वारा पाटन का आश्रय लेने की वजह से ही चीनी रेशम के आयात की मात्रा लगभग 3000 टन से बढ़कर 7000 टन तक (2002-03) पहुंच गयी है।

3. 2ए और इससे ऊपर के ग्रेड का धागा: यह प्रदर्शित करने के लिए किसी किस्म का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अधिकांश भारतीय विनिर्माताओं को 2ए और इससे ऊपर के ग्रेड के रेशम की जरूरत है। साथ ही भारत सरकार ने आयात-निर्यात नीति को उदार बना दिया है और देश में इन ग्रेडों का आयात किए जाने पर कोई प्रतिबंधक नहीं है। जब तक निर्यातक कंपनियां पाटन का आश्रय नहीं लेती हैं और स्थानीय उद्योगों को क्षति नहीं पहुंचती है तब तक रेशम के सभी ग्रेडों का स्वागत है। अतः केवल कीमत के मुद्दे पर विचार किया जाना है। कच्चा रेशम (बिना बटा हुआ) अर्थात् जिसमें बल न दिया गया हो, का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, चाहे वे चीनी कच्चा रेशम हो अथवा भारतीय कच्चा रेशम। तकनीकी रूप से यह कहना ठीक नहीं है कि चीनी रेशम का उपयोग बिना बल दिए किया जा सकता है। करघा प्रचालन के दौरान दबाव को रोकने के लिए बटा हुआ कच्चा रेशम अत्यावश्यक है चाहे वह भारतीय मूल का हो अथवा चीनी मूल का।

4. मांग: यद्यपि रेशम में कई वर्षों से मांग आपूर्ति में अंतराल रहा है, तथापि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह अंतराल 10,000 मी० टन है। यद्यपि चीनी आयात इन वर्षों में 2000 से 3000 मी० टन के आसपास रहा है तथापि वर्ष 2001 के पश्चात यह 5000 मी० टन से अधिक हो गया है और वर्ष 2002-03 के दौरान 7000 मी० टन तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान कई विनिर्माताओं ने चीनी रेशम की बहुत कम कीमत पर पर्याप्त उपलब्धता की वजह से इसके कार्य में लगे रहे। विगत दो वर्षों के दौरान कीमतें 1500 रुपए प्रति किग्रा० से लेकर 1000 रुपए से कम प्रति किग्रा० रहने की वजह से घरेलू उद्योग को कॉफी क्षति हुई है। इसी प्रकार, चीनी रेशम की कीमतें जो कुछेक वर्ष पूर्व बिना (सीमा शुल्क) के लगभग 26 अमरीकी डालर सीआईएफ थी, विगत दो वर्षों के दौरान घटकर 14 अमरीकी डालर से कम हो गयी हैं। यदि केवल चीनी रेशम

की मांग ही इसका कारक होता तो, कीमत कम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती जिससे यह प्रदर्शित होता है कि चीनी कंपनियों ने बदनीयती से पाटन का आश्रय लिया है।

(ख) क्वालिटी सेरीकल्चर सर्विस क्लब:

1. क्वालिटी सेरीकल्चर सर्विस क्लब एक पंजीकृत गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन है जिसकी स्थापना उनके उत्पाद की गुणवत्ता मानक में सुधार करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करने, उत्पाद का गुणवत्ता उन्नयन प्राप्त करते हुए रेशम की खेती के तौर-तरीकों को युक्तिसंगत बनाने के लिए रेशम विज्ञापनी, रेशम के कीड़े के बीज उत्पादकों, सिल्क रीलरों और रेशम हित के लिए एक साझा प्लेटफार्म का सृजन करने के लिए की गयी थी।
2. भारत केवल चीन के बाद विश्व में शहतूती कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम की खेती एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित, ग्रामीण कुटीर उद्योग है जो व्यापक रोजगार का सृजन कर सकता है। अनुमान है कि एक हेक्टेयर शहतूत का बागान वर्ष भर 12 से 13 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर सकता है। श्रम साध्य होने के अलावा रेशम पालन अधिकारों से वंचित एवं भूमिहीन श्रमिकों के लिए एक सर्वोत्तम ग्रामोद्योग है। यह उद्योग उन लघु एवं बहु अत्याधिक छोटे कृषकों के लिए विशेषकर उचित है जो अपने शहतूत उगाते हैं और रेशम कीड़े पालते हैं।
3. अब आधुनिक रेशम उत्पादन के तौर-तरीके परम्परागत रूप से बदलकर गैर-परम्परागत एवं युक्तिसंगत हो गए हैं। रेशम उत्पादन विभाग, केन्द्रीय रेशम बोर्ड और जापानी इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के संयुक्त सहयोग से 2ए + ग्रेड अंतर्राष्ट्रीय रेशम प्रदान करने की क्षमता वाले बिबोल्टीन कोकून की नई किस्मों का पालन करने के लिए भूमि, सिंचाई, बागान एवं भवनों में निजी रेशम विज्ञानियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में निवेश किया गया है।
4. यद्यपि ये नई प्रजातियां शीतोष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त हैं तथापि हम अगस्त से मार्च तक अनुकूल मौसम के दौरान आवश्यक प्रौद्योगिकी का अंगीकरण करके उष्ण कटिबंधीय जलवायु में इन प्रजातियों का सफल पालन करते रहे हैं। इससे इस प्रजाति की कोकून से

- 2ए और इससे ऊपर के ग्रेड के अंतर्राष्ट्रीय रेशम का उत्पादन करना संभव है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रेशम उत्पादकों में इन प्रजातियों की लोकप्रियता बढ़ रही है।
5. यह सच है कि चीन के कुल उत्पादन के मुश्किल से 10 % का उपयोग आंतरिक खपत के लिए किया जाता है और शेष 90 % का निर्यात करके रेशम उत्पादन उद्योग को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाया जाता है। किन्तु हमारे देश में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। सम्पूर्ण रेशम उत्पादन की स्थानीय रूप से खपत होती है और आयातित कच्चे रेशम की खपत करने के लिए भी समय है।
6. आय मार्जिन में तीव्र गिरावट आई थी और वर्ष 2002 के अंत तक रेशम उत्पादन उद्योग में नकारात्मक आय प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति होने के कारण समुचित निवेश करके उन्नत प्रजातियों का लक्षित उत्पादन बढ़ाए जाने से कीमतों में आई गिरावट के कारण अधिकांश रेशम उत्पादकों को अपने शहतूत के बागानों को उखाड़ना पड़ा जिससे केवल कर्नाटक में लगभग 2,73,000 व्यक्तियों को बेरोजगार होना पड़ा।
7. विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें 2ए और इससे निम्न ग्रेड के शहतूती कच्चे रेशम पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गयी थी और इसके पश्चात 2 जनवरी, 2003 को सीमाशुल्क अधिसूचना जारी की गयी थी। इस अधिसूचना के तुरंत बाद कोकून की कीमतों से घाटे की पूर्ति होने लगी। यह बात नोट करना आवश्यक है कि 2001 के दौरान रेशम का कुल आयात लगभग 4,30 मी० टन हुआ था और 2002 के दौरान यह लगभग 6,795 मी० टन (+ 42 %) रहा था। वर्ष 2001 के दौरान रेशमी वस्त्रों का कुल निर्यात 530.21 मिलियन अमरीकी डालर तक का हुआ था किन्तु वर्ष 2002 के दौरान यह 469.22 मिलियन अमरीकी डालर रहा था और इस प्रकार निर्यातों में 8.35 % की गिरावट आई है (विस्तृत विवरण अनुबंध-3 में संलग्न)। उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 के दौरान देश में आयातित रेशम का स्थानीय उपयोग प्रीमियम के लिए बदल दिया गया है। ये आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि आयातों की परेशानी के प्रति कोई न्याय नहीं किया गया है।

8. वस्त्रों में भारत की क्षमता हथकरघा में निहित है जो स्थानीय मल्टीवोल्टीन रेशम पर निर्भर है (पूर्व: कांची, अर्नी, धर्मावरम कांचीपुरम, कोल्काल्मुरु इत्यादि)। रेशम वस्त्रों के उत्पादन में कार्यरत स्थानीय हथकरघा एकक चार परम्परागत पोशाक समायोत्री के लिए मोल्टीवोन रेशम की खपत कर रहे हैं। ग्रेडरहित आयातित रेशम की मुक्त उपलब्धता के कारण इन इकाईयों ने मल्टीवोल्टीन रेशम की खपत एवं मिश्रण करना शुरू कर दिया है जिससे परम्परागत वस्त्रों को अधिक क्षति हो रही है।
9. हम आपका ध्यान तुरंत हस्तक्षेप हेतु चीन के निर्यातकों द्वारा आपके दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 के आदेश की जानबूझ कर परिवर्चना करने के प्रयासों जिसमें भारत को किए गए वास्तविक सभी निर्यातों को 3ए और उससे अधिक के ग्रेड की संज्ञा दी गयी है, की ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे। यह मानदण्डों का घोर उल्लंघन है और हम अन्य देशों से आयातित रेशम के सभी ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हैं। शुल्क में छूट के लिए केवल अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम पर विचार किया जा सकता है जिसमें आयातों का उपयोग वापसी निर्यात के लिए किया जाता है न कि डीएफआरसी और डीईपीबी के तहत किया गया आयात के लिए जिसमें शुल्क मुक्त रेशम कीमतों को रोकने के लिए बाजार में भेजा जाता है।

(ग) रेशम निदेशक, पश्चिम बंगाल के विचार

1. कोकून और रेशम बाजार में चल रही मंदी जो हाल ही में खतरनाक स्तर तक पहुंच गयी है, रेशम उत्पादक सभी राज्यों खासकर पश्चिम बंगाल के लिए एक अत्यन्त गंभीर चिंता का विषय है। पड़ोसी देशों के साथ अपनी निकटता की वजह से यह राज्य चीनी रेशम की अंधाधुंध बाढ़ से उत्पन्न इस स्थिति का सबसे अधिक शिकार हुआ है जो रेशम की तुलना में कोकून की कीमत में गिरावट के रुख से स्पष्ट है। कोकून की कीमत में अप्रत्याशित गिरावट के साथ ही अनेक शहतूत उत्पादकों में अपने बागानों को नष्ट करने और इस खेती को छोड़कर कोई अन्य खेती करने की प्रवृत्ति रही है जिससे इस अति प्राचीन परम्परागत कृषि आधारित कुटीर उद्योग के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया है।
2. भारत सरकार द्वारा पाटनरोधी उपाय करना एक अति न्यायोचित समुचित एवं समय पर की गयी पहल है जिसे भविष्य में जारी रखे जाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया के सकारात्मक

परिणामस्वरूप बाजार में घरेलू कोकून और कच्चे रेशम की कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जिससे रेशम उत्पादकों में विश्वास, हौसला एवं उत्साह बहाल होने की आशा है।

3. पड़ोसी देशों की सीमा पार से विदेशी रेशम की तस्करी तब तक अबाधित जारी रहेगी जब तक कि कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों द्वारा इस अवैध व्यापार के विरुद्ध कोई कड़े उपाय सुनिश्चित नहीं कर लिए जाते हैं।
4. सीएसबी की रेशम अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों एवं तौर-तरीके के पैकेज को इस क्षेत्र में लागू किया जा रहा है ताकि उत्पादकता एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके जिससे भविष्य में अपने उत्पाद की लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादकों को मदद मिलेगी।

(घ) सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है। सभी ने आयात किए जा रहे कच्चे रेशम के ग्रेडों, चीनी और भारतीय धागे की प्रतिस्थापनीयता, आयातित चीनी कच्चे रेशम की कीमत एवं मांग स्तर के बारे में प्रश्न किए हैं। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि देश में विभिन्न ग्रेडों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक वर्तमान जांच का संबंध है, जांचाधीन उत्पाद के दायरे को केवल 2ए और इससे निम्न ग्रेड तक ही सीमित किया गया है। विगत दो वर्षों के दौरान चीनी रेशम का उपयोग अति निम्न कीमत पर उपलब्धता की वजह से बिजली करघा और हथकरघा दोनों में किया गया है। इसके अलावा, कच्चे रेशम का उपयोग बिना बटे हुए अर्थात् मूल पर विचार किए बिना बटा हुआ की दशा में नहीं किया जा सकता है।

जांचाधीन अवधि के दौरान कच्चे रेशम की मांग लगभग 9,400 मी० टन की थी और आपूर्ति व मांग के बीच का अंतर केवल लगभग 3,700 मी० टन का था। प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि चीन से संबद्ध माल का आयात 4,930 मी० टन अधिक रहा है जो जांचाधीन अवधि के पश्चात अप्रैल 2003 से जनवरी 2003 (10 महीनों) के दौरान बढ़कर 5,293 मी० टन हो गया है। संबद्ध माल की चीनी सी आई एफ कीमत जो जांच अवधि के दौरान ***रु०/किग्रा०

थी वह जांचावधि के पश्चात घटकर *** रुपए/किग्रा० हो गयी है (अर्थात् 22 %) लगभग *** रुपए/किग्रा० की भारित औसत पहुंच कीमत पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि संबद्ध माल के प्रयोक्ताओं द्वारा इस कीमत पर आयात किया जा रहा था।

5. (ड.) हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां

मैसर्स चामुंडी टेक्सटाइल्स लि०, सिल्क वीवर्स सोसाईटीज सिल्क ट्रेड एसोसिएशन, वाराणसी वस्त्र उद्योग संघ और अन्य जो सभी संबद्ध माल के आयातक हैं, से प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उठाए गए मुद्दों में से कुछ मुद्दों पर उपर्युक्त पैरा (घ) में कार्रवाई की गई है।

(i) उन्होंने यह बात नोट की है कि प्राधिकारी ने जांच के दायरे को केवल 2ए ग्रेड और इससे निम्न ग्रेड तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया है।

(ii) उन्होंने यह बात नोट की है कि प्राधिकारी ने सभी 17 प्रतिवादी निर्यातकों के प्रश्नावलीगत उत्तर अस्वीकार कर दिए हैं और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने प्राधिकारी से निवेदन किया है कि वह डब्ल्यू टी ओ करार के अनुबंध - II के पैराग्राफ 7 के अनुसार प्राधिकारी के दायित्वों पर ध्यान दें।

(iii) उन्होंने यह बात नोट की है कि पाटन मार्जिन और पाटन मार्जिन निकालने के लिए अपनायी गयी पद्धति का विस्तृत उल्लेख प्रकटीकरण विवरण में किया गया है। उन्होंने उस प्रत्येक लागत की मद का आधार एवं ब्यौरा देते हुए जो नुकसान रहित कीमत निकालने में शामिल की गयी है, उन तत्वों का खुलासा करने का अनुरोध किया है जिन पर नुकसान रहित कीमत निकालते समय विचार किया गया है।

(घ) प्रकटीकरण विवरण प्राप्त टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा जांच

(i) वर्तमान मामले में जांचाधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य अथवा वहां से निर्यातित शहतूती कच्चा रेशम (बिना बटा हुआ) है जो 2ए ग्रेड और उससे निम्न ग्रेड का है।

(ii) प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार गौण स्रोत अथवा याचिका में प्रस्तुत सूचना नहीं रहा है बल्कि मूल देश में उत्पादन की अनुमानित लागत, प्रशासनिक और सामान्य व्यय और उचित समायोजन, जो चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध माल का सामान्य मूल्य निकालने के आधार के रूप में लिए गए हैं, करने के पश्चात उचित लाभ राशि के बारे में उपलब्ध सूचना रही है।

(iii) चूंकि नुकसानरहित कीमत का आधार लागत संबंधी वे कारक हैं जो घरेलू उद्योग के गोपनीय हैं इसलिए लागत की प्रत्येक मद का आधार और उसका ब्यौरा देना संभव नहीं है।

च. पाटन:-

1. उद्गम के देश में संबद्ध वस्तु के निर्यातक तथा उत्पादक -

प्राधिकारी ने धारा 9 क (1) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के वे निर्यातक, जिन्होंने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में जानकारी दी है, विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माता/उत्पादक नहीं हैं बल्कि निर्यातक/व्यापारी हैं। परिणामतः उत्तर में उनके परिशिष्ट 1 के अनुसार घरेलू बिक्रियों के ब्योरे तथा निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट 8,9 तथा 10 में दिए गए प्रपत्रों में यथा अपेक्षित संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत संबंधी ब्योरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर महत्वपूर्ण परिशिष्टों की दृष्टि से अपर्याप्त है।

प्रारंभिक जाँच परिणामों में प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर व्यापारिक कंपनियों ने दिया है जिनके पास संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए कोई उत्पादन सुविधा नहीं है। इन कंपनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए आग्रह किया है। इस मामले में चीन जनगण0के 17 में से कुल 11 प्रतिवादियों ने अपने को राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी बताया है। तथापि, इन कंपनियों द्वारा उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्रियों के संबंध में प्रश्नावली के संगत परिशिष्टों में जानकारी नहीं दी गई है। और न ही उन्होंने प्रारंभिक जाँच परिणामों के समय पैरा 8 के उप पैरा (3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दर्जा प्रदान करने के संबंध में कोई सूचना साक्ष्य प्रस्तुत किया था। चूंकि उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्रियों के संबंध में आंकड़ें प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के उप-नियम 2(1) और (ii) के साथ पाठित धारा 9क(1)(ग)(1) और (ii) में निहित प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका और प्राधिकारी को प्रारंभिक जाँच परिणामों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करने को बाध्य होना पड़ा था।

चीन के निर्यातक उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए प्राधिकारी ने सभी 17 सहयोगी कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली भेजी जिससे वे यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। स्वामित्व, प्रबंधन नियंत्रण, वाणिज्यिक तथा व्यवसायिक नीतियों के निर्धारण तथा वित्तीय स्थिति के संबंध में ब्योरे वार प्रश्न इन कंपनियों को प्रेषित किए गए। प्रतिवादियों से मलबेरी रां सिल्क की उत्पादन लागत तथा निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट 1 अर्थात् घरेलू बाजार में बिक्रियों से संबंधित सूचना, में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार चीन में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों द्वारा जाँच अवधि के दौरान चीन जनगण0 में घरेलू बाजार में सभी सौदे-वारं घरेलू बिक्रियों की प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था। प्राधिकारी ने इनमें से 13 प्रतिवादियों से प्राप्त उत्तरों की यह निर्धारण करने के लिए जाँच की है कि क्या इन कंपनियों के पास राज्य से एक स्तर तक स्वतंत्रता थी तथा इन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रचलित स्थितियों से तुलनीय बाजार स्थितियों में प्रचालन किया था।

प्रस्तुत की गई सूचना यह दर्शाती है कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के 13 प्रतिवादियों में से 9 राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। यद्यपि प्रतिवादियों ने ये बताया है कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में कोई सरकारी अधिकारी नहीं होता है, परन्तु वास्तविक शेयर धारकों के संबंध में कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। यद्यपि इसमें वियोजन तथा प्रबंधकीय प्राधिकरण के बारे में बताया गया है, तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि उद्यम किस प्रकार से राज्य के स्वामित्व वाली सम्पत्ति को उपयोग तथा निपटान कर सकता है और इन उत्तरों से यह निर्धारित नहीं होता है कि राज्य किस तरह से इन कंपनियों के व्यवसायिक प्रचालन में हस्तक्षेप नहीं करता है।

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के 13 प्रतिवादियों में से 5 व्यापारिक कंपनियों ने उत्पादकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है, शेष 8 प्रतिवादियों के मामले में उत्पादकों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। 2 कंपनियों (चोगक्विंग गोल्डन सिल्क तथा जियांग सू सोहो) तथा उनके उत्पादकों को छोड़कर, शेष सभी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियाँ हैं। इसलिए राज्य के हस्तक्षेप के न होने की गारंटी नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त 2 कंपनियों के मामले में घरेलू बिक्रियां या तो बतायी नहीं गई हैं या फिर क्रेताओं के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। चेंगडू तियांन्यू को छोड़कर शेष 6 कंपनियों के लिए अन्य कंपनियों ने या तो घरेलू बिक्रियां नहीं बतायी हैं या घरेलू बिक्री के संबंध में अपूर्ण जानकारी दी है आकरैर उनकी उत्पादन लागत भी प्रस्तुत नहीं की है। निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट 8 के अंतर्गत यथाअपेक्षित उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों की अनुपस्थिति में, यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह बिक्रियां व्यापार के सामान्य क्रय मर्के की गई हों। संबद्ध वस्तु के एक सहयोगी उत्पादक सिचुआन न्यू सेंचुरी इंडस्ट्रीज कं० लि० के संबंध में दी गई घरेलू बिक्री संबंधी सूचना यह दर्शाती है कि सभी बिक्रियां संबद्ध/सहयोगी कंपनी अर्थात् मै० चेन्गडू तियांन्यू कोई की गई हैं आकरैर इस प्रकार ये व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं हैं क्योंकि ये असंबद्ध सौदे नहीं हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और यद्यपि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में उत्पादकों द्वारा कुछ मामलों में घरेलू बिक्रियों संबंधी सूचना प्रस्तुत की गई है, परन्तु यह प्रदत्त सूचना केवल संबंधित/संबद्ध निर्यातक या क्रेताओं जिनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है की गई बिक्रियों के संबंध में है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या इसमें जाँच अवधि के दौरान हुई सभी घरेलू बिक्रियों संबंधी सौदे शामिल हैं। चूंकि निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट 8 के अंतर्गत यथा अपेक्षित उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं इसलिए यह ज्ञात नहीं है कि क्या ये बिक्रियां व्यापार के सामान्य क्रम में हुई हैं।

चीन की वे व्यापारिक कंपनियां जिन्होंने निर्यातक प्रश्नावली और तत्पश्चात् बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली का उत्तर दिया है, ने बाजार अर्थव्यवस्था/व्यक्तिगत व्यवहार के लिए अनुरोध किया है। मात्राओं तथा ऐसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के जरिए भारत को बिक्री के नियम एवं शर्तों का संबंध है ये कंपनियां राज्य के हस्तक्षेप की गैरमौजूदगी को पर्याप्त रूप से सिद्ध करने में असमर्थ रही थीं। प्रमुख निविष्टियों/उपयोगों की लागत इनकी बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती हुई प्रतीत नहीं होती हैं क्योंकि इनकी खरीद या तो सामूहिक स्वामित्व वाली या राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों से की गई है। कुछ प्रत्युत्तरों में घरेलू बाजार में बेची गई मात्राएं तथा संबद्ध वस्तु की प्रति इकाई कीमत मोटे तौर पर एक समान हैं। कच्ची सामग्री की खरीद की पद्धति तथा उपयोग एवं बेची गई

मात्राओं और इनकी कीमतें अनुबंध 1, पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में उल्लिखित मापदण्डों की पूरा नहीं करते हैं। इसके अलावा इनमें से अधिकतर कंपनियों की पूंजी राज्य के स्वामित्व में है। इसकलिए व्यापारिक कंपनियों/उत्पादकों द्वारा किए गए अनुरोधों से निष्कर्षतः यह सिद्ध नहीं होता है कि ये कंपनियाँ राज्य के स्वामित्व से अलग स्वतंत्र रूप से तथा बाजार के संकेतकों के अनुसार प्रचालनरत हैं, कि क्या ये कीमतें, लागतें तथा कच्ची सामग्री सहित निविष्टियों संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाते हैं, कि क्या प्रौद्योगिकी तथा श्रम (वेतन तथा कर्मचारियों की संख्या), उत्पादन के स्तर, कीमत निर्धारण निवेश तथा घरेलू एवं निर्यात बाजारों में बेची गई मात्राओं के संबंध में पूर्ति तथा मार्गों को देखते हुए बाजार संकेतकों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। कुछ मामलों में यह बताया गया है कि इन कंपनियों के लिए हर वर्ष अपने वित्त विवरणों की लेखा परीक्षा कराने का ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। छोटे पैमाने तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके विवरण लेखा परीक्षा के अधीन रखना अपेक्षित नहीं है। प्राप्त उत्तरों से यह निर्धारण नहीं किया जा सका कि क्या ये कंपनियाँ यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1, पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं।

(क) सामान्य मूल्य

प्रारंभिक जाँच परिणामों में पैरा 4(क) से 4(थ) तक प्रत्येक चीनी निर्यातक के विवरणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तथापि, उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्रियों के संबंध में प्रश्नावली के संगत परिशिष्टों में इन कंपनियों द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल एक निर्यातक मै 0 चेंगडू तियानयू सिल्क कं 0 लि 0, जो चीन जन गण के कंपनी कानून के अनुसार स्थापित एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है तथा जिसके पास सिचुआन न्यू सेंचुरी सिल्क इंडस्ट्रीज कं 0 लि 0 संबंधित उत्पाद के एक उत्पादक के ज्यादातर शेयर हैं, ने बिक्री के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है, जबकि उत्पादन लागत के संबंध में आंकड़ें सिचुआन न्यू सेंचुरी द्वारा तैयार किए गए हैं। मै 0 चेंगडू तियानयू तथा इसके संबद्ध उत्पादक सिचुआन न्यू सेंचुरी सिल्क इंडस्ट्रीज कं 0 लि 0 ने तत्पश्चात् बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली का भी उत्तर दिया है।

प्राधिकारी द्वारा चेंगडू तियानयू/सिचुआन न्यू सेंचुरी सिल्क इंडस्ट्रीज के बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रत्युत्तर की जाँच

1. चेंगडू तियानयू, जो एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, के 19 शेयर धारक हैं। चेंगडू तियानयू डेवलपमेंट कं 0 लि 0 के पास 50% शेयर हैं जबकि बाकी शेयर प्रकृत व्यक्तियों के पास हैं। सिचुआन न्यू सेंचुरी सिल्क इंडस्ट्रीज जो उत्पादक है, को एक पूर्णतः निजी स्वामित्व के अधीन सीमित दायित्व वाली कंपनी बताया गया है। शेयर धारकों की सूची यह दर्शाती है कि चेंगडू तियानयू के पास 66.7% शेयर हैं जबकि 33.3% शेयर राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के पास हैं।
2. उत्पादक ने जाँच अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के प्रमुख आपूर्ति कर्ताओं के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। इसमें कोकून के किसान (85% खरीद), एक कंपनी से

- 3.7% खरीद जकसका नाम नहीं बताया गया, और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी से 2.6% खरीद शामिल है। ~~खरीद~~ की पद्धति मौके पर सौदे को बताया गया है। उत्पादक कोकून किसानों से ताजा-कोकून खरीदता है तथा इन्हें सूखाकर ताजे कोकून से सूखे कोकून बनाता है।
3. उत्पादन सुविधाओं के संबंध में, बिजली की आपूर्तिकर्ता कंपनी दीर्घावधि संविदा के तहत एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी थी। बिजली की इकाई लागत *** आरएमबीयूआन/कि०वा०/घंटा है। पानी को नदी से लिफ्ट पम्प द्वारा पम्प किया जाता है तथा बिजली को लागत के साथ परिकलित उत्पादक कोयले द्वारा भाप बनाते हैं जिसे कथित तौर पर लागत में जोड़ दिया गया है। जल तथा भाप की इकाई लागत प्रस्तुत नहीं की गई है। कोयले की खरीद एक दीर्घावधि संविदा के तहत एक निजी उद्यम से की जाती है। कोयले की प्रति इकाई कीमत *** आरएमबीयूआन/मी०टन बताई गई है।
4. कर्मचारियों की संख्या *** बताई गई है जिसमें से ~~25~~ व्यक्ति कुशल तथा अकुशल मजदूर हैं, ~~25~~ प्रबंधन कार्मिक हैं तथा प्रबंधक हैं। औसत वेतन *** आरएमबी वार्षिक है।
5. घरेलू बाजार में उत्पादक द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों के संबंध में जानकारी दी गई है। बेची गई कुल मात्रा *** मी०टन है जिसका मूल्य *** आरएमबी है जो आरएमबी *** /मी०टन बैठता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये सभी बिक्रियां संबद्ध/सहयोगी कंपनी मै० चेम्बू तियानयू को की गई है और ये बिक्रियां हैं। इस प्रकार ये बिक्रियां व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं हैं क्योंकि ये असंबद्ध बिक्रियां नहीं हैं।
6. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में अपने प्रारंभिक जांच परिणामों का स्मरण करते हैं। प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने नोट किया था कि दावा की गई उत्पादन लागत *** अमरीकी डालर/कि०ग्रा० है। उत्पादन लागत में ~~25~~ कि०ग्रा० के कुल उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोकून की कुल मात्रा (*** कि०ग्रा०) उत्पादन के *** कि०ग्रा० प्रति इकाई (कि०ग्रा०) बैठती है। यह रेनडिट्टा स्तर आमतौर पर सर्वोच्च भारतीय रेजडिट्टा स्तर *** कि०ग्रा० प्रति इकाई की तुलना में कम होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कोकून की लागत कुल उत्पादन लागत का 71.3% बनती है और दावा किया गया ख़त स्तर आम तौर पर कम है। प्रारंभिक जाँच परिणामों के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने जुलाई 2001 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जो जाँच अवधि नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण में घरेलू बाजार में औसत घरेलू बिक्री कीमत *** अमरीकी डालर/कि०ग्रा० है जो कंपनी द्वारा दावा की गई उत्पादनलागत से कम है और इस प्रकार घरेलू बिक्री सौदे व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं किए गए हैं।
7. प्रारंभिक जाँच परिणामों के समय निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में तथा उसके पश्चात बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में यथा प्रस्तुत उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्रियां संबंधी आंकड़ों की निम्नांकित तालिका के अनुसार जाँच की गई है।

	निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में	बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली	निर्यातक प्रश्नावली के
--	----------------------------------	--	------------------------

1.	यथाप्रस्तुति	के उत्तर में यथा प्रस्तुत	उत्तर तथा एमईटी उत्तर में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच अंतर
2.	3.	4.	
उत्पादन जुलाई 2001 से मार्च 2002 (कि.ग्रा.)	अ. नं. (सभी ग्रेड)	संबंधित उत्पाद	-178441
कोकून खरीदे गये/प्रयुक्त(कि.ग्रा.)	***	***	***
कोकून दर/आरएमबी/कि.ग्रा.	***	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
रेनडिट्टास्तर	***	***	***
कच्ची सामग्री की लागत	***		
प्रत्यक्ष श्रम (आरएमबी)	***	***	***
प्रत्यक्ष श्रम (आरएमबी प्रति कि०ग्रा०)	***	***	***
उपयोगिताएं (जल, विद्युत तथा कोयला) आर.एम.बी./कि.ग्रा.	***	यद्यपि बिजली का औसत मूल्य *** आरएमबीयूआन/कि०ग्रा०/घंटा बताई गई है, परन्तु कच्चे रेशम के प्रति/कि०ग्रा० पर आवश्यक बिजली की खपत नहीं बताई गई है। कोयले की औसत कीमत *** आरएमबी/मी.टन बताई गई है, परन्तु कच्चे रेशम के प्रति कि०ग्रा० कोयले की खपत को बताया गया है। पानी की दर तथा खपत नहीं बताई गई है।	
रूपांतरण लागत	*** आरएमबी/कि.ग्रा.	***	***
अवमूल्यन	***	***	***
डीईपीएन	***	***	***

आरएमबी/कि. ग्रा.			
ब्याज सहित वित्त प्रबन्ध लागत	***	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पैकिंग लागत	***	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
बिक्री लागत	***	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
प्रशासनिक लागत	***	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सीओएनएस कर बिक्री कर	***	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल लागत	आरएमबी ***		
लाभ	आरएमबी***		
बिक्री कीमत	आरएमबी*** अमरीकी डालर***		

प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों के समय उत्पादन तथा कम्पनी द्वारा दावा किए गए रेनरडिटा स्तर क्रमशः *** कि०ग्रा० तथा *** था और एमआईटी प्रश्नावली के उत्तर में क्रमशः *** कि०ग्रा० तथा *** था। प्रत्येक लागत घटक के संबंध में कोई समर्थकारी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रस्तुत आंकड़ों में गंभीर असंगतियाँ हैं जिनका इन जांचों में प्रभावित चीन जनमाणसे सार्स के तीव्र भय के कारण, सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के लिए चेन्डू टियानू की घरेलू बिक्री कीमतें दावा किए गए उत्पादन लागत से कम हैं और इसलिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं। उत्पादक की घरेलू बिक्रियाँ इसके संबद्ध कम्पनी अर्थात् चेन्डू टियानू को की गई हैं तथा इसलिए आम्स लेन्थ के मामले नहीं हैं। प्राधिकारी इसलिए चेन्डू टियानू/सिचुआन न्यू सेन्चुरी द्वारा उत्पादन लागत के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को उपयुक्त सभी कारणों से अस्वीकार करने को बाध्य हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि इस जांच में उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्रियों के संबंध में 16 अन्य प्रतिवादियों द्वारा आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए हैं तथा चूंकि मै. चेंगडु तिआनयू/सिचुआन न्यू सेन्चुरी सिल्क इंडस्ट्रीज के मामले में उपर्युक्त कारणों से उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े स्वीकार योग्य नहीं हैं, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के उप-नियम 2(i) तथा(ii) के साथ पठित धारा 9क(1)(ग)(1) तथा (ii) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी इसलिए पैरा 1 से 6 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थ हैं तथा उपलब्ध तथ्यों के अनुसार कार्रवाई करने को बाध्य हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में नियमों के तहत सामान्य मूल्य का निर्धारण नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है। इसलिए मूल देश में अनुमानित उत्पादन लागत के संबंध में उपलब्ध सूचना तथा बिक्री प्रशासनिक तथा सामान्य खर्च और उचित समायोजनों के पश्चात उचित लाभ की राशि को चीन जन.गण में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया है जो कि इसलिए जांच अवधि के दौरान 1 अमरीकी डालर=47.54 रूपए के औसत विनिमय दर पर *** अमरीकी डालर/किग्रा अथवा *** रूपए/किग्रा विचार किया गया है।

(ख) निर्यात कीमत

प्रारंभिक जांच परिणामों के समय प्राधिकारी ने इन जांचों में चीन से प्रतिवादियों के लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली के सामान्य खंड के क्रमांक 5 के अनुसार जहां कहीं भी दावा किया जाता है तो सामान्य मूल्य तथा नियत कीमत के लिए दावा किए गए कीमत समायोजनों के संबंध में साक्ष्य संलग्न किए जाने चाहिए। तथापि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को संगत साक्ष्यों के साथ प्रमाणित नहीं किया गया था। प्राधिकारी अग्रे नोट करते हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन से आयात की कुल मात्रा चीनी निर्यातकों द्वारा बताई गई मात्रा से काफी अधिक है। प्राधिकारी इसलिए नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित करने को बाध्य हैं।

एक निर्यातक द्वारा किए गए निम्नलिखित समायोजनों पर विचार करने के पश्चात पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तहत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है।

पैकिंग आर एम बी ***/किग्रा=***अमरीकी डालर/किग्रा, अंतर्देशीय भाड़ा आर एम बी ***/किग्रा=***अमरीकी डालर/किग्रा, भंडारण आर एम बी ***/किग्रा=***अमरीकी डालर/किग्रा, हैंडलिंग आर एम बी ***/किग्रा=*** अमरीकी डालर/किग्रा, बट्टा/कमीशन- *** अमरीकी डालर अथवा *** अमरीकी डालर/किग्रा, बीमा *** अमरीकी डालर या ***अमरीकी डालर/किग्रा, समुद्री भाड़ा *** अमरीकी डालर या *** अमरीकी डालर/किग्रा।

प्राधिकारी के पास उपलब्ध डी जी सी आई एंड एस के सरकारी आंकड़ों के अनुसार *** रूपए के सी आई एफ मूल्य की संबद्ध वस्तुओं की 49,29,632 किग्रा की मात्रा का जांच अवधि के दौरान (अप्रैल, 2001-मार्च 2002) चीन जन.गण. द्वारा निर्यात किया गया था। इसलिए सी आई एफ कीमत *** रूपए/किग्रा है। ऊपर दावा किए गए समायोजनों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी ने कारखाना

द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण किया है । इसलिए कारखाना-द्वार पर निर्यात कीमत *** अमरीकी डालर/किग्रा परिकलित होती है ।

ग. पाटन मार्जिन

*** अमरीकी डालर/किग्रा पर निर्मित सामान्य मूल्य तथा *** अमरीकी/किग्रा पर कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन ***अमरीकी डालर/किग्रा बनता है (जो कि निर्यात कीमत का 47.89% है) ।

(छ). क्षति

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत, जब क्षति का जांच परिणाम निकाला जाता है तो, ऐसे जांच परिणाम में पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण शामिल होता है । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को किसी खास सीमा तक रोकना या कीमत वृद्धि को रोकना है, जो कि अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन का मार्जिन तथा संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा उपरोक्त नियम 11 में निर्धारित सीमा से अधिक है ।

प्राधिकारी ने जांच अवधि और पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में विभिन्न रीलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले घरेलू उद्योग से लागत संबंधी सूचना की निर्धारित प्रपत्र में मांग की । घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन लागत का उपयोग सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांत (गैप) के आधार पर उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए किया गया है ।

घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी के निर्धारण में प्राधिकारी ने कच्ची सामग्रियों के उपयोग, उपयोगिता के इस्तेमाल जांच अवधि के दौरान वास्तविक खर्च निवेश क्षमता उपयोग आदि सहित सभी संगत कारकों का उचित विश्लेषण घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निकालने के लिए किया है । घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी का निर्धारण लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ मार्जिन पर विचार करते हुए किया गया है ।

भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने उत्पादन के रूप उद्योग की दशा, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण एवं मार्जिन आदि से संबंध रखने वाले ऐसे संकेतको पर उपर्युक्त नियम के अनुबंध II (iv) के अनुसार विचार किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(क) आयातों की मात्रा

स्रोत: डीजीसीआईएस

	2000-2001	2001-2002 (12 महीने जांच अवधि)
अलग-अलग देश से निर्यात (एम टी)		
चीन जन.गण.	3161	4929.632
संबद्ध देश (कुल)	3161.346	4929.632
अन्य स्रोत (कुल)	286.815	393.317
कुल आयात (एम टी)	3448.161	5322.949

2000-2001 में आयातों की मात्रा की तुलना में जांच अवधि में चीन जन.गण. से शहतूती कच्चे रेशम के कुल आयातों में हुई वृद्धि 55.95% की थी।

कुल आयातों में चीन जन.गण. का हिस्सा 2000-01 में 91.68% था तथा 2001-02 (12 महीने जांच अवधि) में 92.61% था।

अप्रैल 2002 जनवरी 2003 की अवधि के लिए संकलित डी जी सी आई एस के आंकड़ों के अनुसार चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा 52,92,722 किग्रा थी जिसकी कीमत 384,09,00,873 रूपए थी जिससे जांच अवधि के पश्चात सी आई एफ कीमत में 725.69 ₹/किग्रा की अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित हुई।

(ख) उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

याचिकाकर्ताओं की उत्पादन क्षमता वास्तविक उत्पादन तथा क्षमता उपयोग निम्नानुसार था:-

याचिकाकर्ता	2000-01	2001-02 (12 महीने जांच अवधि)
स्थापित क्षमता (बेसिनों की सं.)	25,456 बेसिन	26,822 बेसिन
स्थापित क्षमता (एम टी)	7255	8408
उत्पादन (एम टी)	6546	5663
क्षमता उपयोग %	90% लगभग	60% लगभग

जांच अवधि के दौरान सदस्यों/इकाइयों की संख्या, रीलिंग बेसिनों की संख्या तथा कुल कच्चे सिल्क उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

	एसोएसिशन का नाम तथा पता	सदस्यों/इकाइयों की सं.	रीलिंग बेसिनों की सं.		कुल कच्चे रेशम का उत्पादन (एम टी)
			कॉलेज	मल्टीन्ड	
1	सभी सिल्क रिलर्स एसोसिएशन	360	1900	300	484

	कोकून बाजार के पास कोलर 563101				
2	कोलर सिल्क रिलर्स इंडस्ट्री आल को आपरेटिव सोसाइटी लि०, कोलर	80	580	100	153
3	रामानगरम सिल्क रिलर्स वेल्फेयर एसोसिएशन, रामानगरम	1460	9300	---	1784
4	कर्नाटक स्टेट मल्टीन्ड सिल्क रिलर्स वेल्फेयर एसोसिएशन रामानगरम	43	---	410	75
5	दि प्रोग्रेसिव सिल्क रिलर्स इंडस्ट्रीअल को ऑपरेटिव सोसाइटी लि० सिदलाघट्टा	860	5218	210	994
6	तमिलनाडु स्टेट मल्टीन्ड रिलर्स एसोसिएशन धर्मापुरी	15	---	136	34
7.	दि पैलाकोड सिल्क रिलर्स एसोसिएशन पैलाकोड	57	340	---	84
8	कोयम्बटूर डिस्ट्रीक्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कोयम्बटूर	95	568	---	142
9	आंध्र प्रदेश •आंध्र प्रदेश में कोई एसोसिएशन नहीं है।	1176	6920	840	1912
	कुल	4145	24826	1996	5663

(ग) बिक्री तथा बाजार हिस्सा

	2000-01	2001-02(12 महीने जांच अवधि)
याचिकाकर्ताओं की बिक्रियां	6546	3397.8(लगभग 48.09% की गिरावट)
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	669	676
कुल बिक्रियां	7216	4073.8
मांग	10,664	9396.7
मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा	61.39%	36.16%
मांग में आयातों का हिस्सा	32.33%	56.64%
पाटित आयातों का हिस्सा	29.64%	52.46%

यह देखा गया है कि पाटित आयातों में पूरे अर्थों में वृद्धि हुई है। जबकि चीन जन.गण. से मांग में आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है तथा मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है।

(घ) कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास

रूपए/किग्रा

वर्ष	बिक्री प्राप्ति(रूपए/किग्रा)	आयातों का पहुंच मूल्य	
		चीन जन.गण.	अन्य
2000-01	***	***	1371
2001-02(जांच अवधि)	***	***	1236
जांच अवधि के पश्चात (2002-2003)	***	***	

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि चीन जन.गण. से निर्यातकों ने जांच अवधि में अपनी कीमते उल्लेखनीय रूप से घटाई है। घरेलू उद्योग को बाजार में कम आयात कीमतों का उत्तर देने के लिए अपनी बिक्री कीमतें घटाने को बाध्य किया गया है।

(ड.) लाभप्रदता

याचिकाकर्ता	2000-01	2001-02 (12 महीने-पी ओ आई)
सी ओ पी	***	***
बिक्री कीमत	***	***
पी/एल	(***)	(***)

जांच अवधि में याचिकाकर्ताओं के घाटे में वृद्धि हुई है।

(च) अंतिम स्टॉक

(किग्रा)

	2000-01	2001-02(12 महीने पी ओ आई)
याचिकाकर्ता	10%	40% (2265.2 एम टी लगभग)

(छ) विक्रियों में वास्तविक तथा संभावित कमी

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया, घरेलू बिक्री की मात्रा 2000-01 में 6546 मी. टन से घटकर

जांच अवधि के दौरान 3397.8 (लगभग 47.९१%) की गिरावट) हो गया। इस प्रकार बिक्रियों की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई थी।

(ज) उत्पादकता

पिछले दशक में रेनडिटा(1 किग्रा कच्चा सिल्क पैदा करने के लिए उपभोग किए गए ककून की मात्रा) जो कि उत्पादकता का सूचक है, 12 से घटकर 7 हो गया इस प्रकार घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। ऐसा इस क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों द्वारा नई अत्यधिक उत्पादक प्रजातियों के प्रवेश कराए जाने के कारण हुआ। तथापि बाजार में चीन के सस्ते सिल्क की उपलब्धता के कारण शहतूत का काफी उन्मूलन हुआ है तथा जांच अवधि के दौरान तथा बाद में शहतूत एक्रिएज का अपकर्ष हुआ।

(झ) उत्पादन

2000-01 के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन 6546 मी.टन था। यह जांच अवधि के दौरान घटकर 5663 मी.टन हो गया।

(ञ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

कच्चे सिल्क का बाजार बहुत ही प्रतिस्पर्धी है। वैश्विक रूप से चीन जन.गण. मुख्य उत्पादक हैं तथा भारत में विभिन्न ग्राहकों के लिए निम्न स्तर की कीमतें इंगित करता रहा है। घरेलू उद्योग को या तो कम कीमतें उद्धृत करनी होगी या बिक्री की मात्रा गंवानी होगी। दुर्भाग्याश, घरेलू उद्योग आयातित संबद्ध वस्तुओं की सीमा तक कीमतें घटाने की स्थिति में नहीं है। इस लिए यह अपनी बिक्रियों की मात्रा गंवा रहा है तथा बहुत सी इकाइयों को व्यवसाय छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है। शहतूत के खेतों का भी उन्मूल कर दिया गया है तथा किसान रेशम उत्पादन को छोड़कर अन्य कार्य कलापों में लग गए हैं। कोई और अन्य कारक नहीं है जिसने महत्वपूर्ण सीमा तक घरेलू कीमतों को प्रभावित किया हो।

(ट) पाटन मार्जिन की मात्रा

संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन 47.89 % है। अतः पाटन मार्जिन की मात्रा महत्वपूर्ण ढंग से अधिक है तथा इसके कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है।

(ठ) रोजगार तथा मजदूरी

जांच अवधि के दौरान करीब 1633 इकाईयां तथा जांच अवधि के बाद 2500 इकाईयां बंद थी। इस प्रकार जांच अवधि के दौरान करीब 20000 मानव दिन तथा जांच अवधि के बाद 30000 मानव दिन की हानि हुई।

(ड) विकास तथा पूंजी जुटाने की क्षमता

घरेलू उत्पादन वाली इकाईयों में जीवतता के कोई लक्षण नहीं हैं। पाटित आयातों के कारण घरेलू उत्पादकों के बिक्री की मात्रा में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग कोई भी महत्वपूर्ण पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं रही है क्योंकि जांच अवधि के बाद भी संकट जारी है।

विभिन्न रीलर्स संघ के अधीन जांच अवधि के दौरान बंद किए गए रीलिंग इकाईयों की संख्या निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	संघ के नाम तथा पते	कार्यरत इकाईयों की संख्या	बंद इकाईयों की संख्या
1.	ऑल सिल्क रीलर्स एसोसिएशन कोकुन मार्केट के समीप, कोलार-563101	240	120
2.	कोलार सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, कोलार	55	25
3.	रामानगरम सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन रामानगरम	802	658
4.	कर्नाटका स्टेट मल्टीएंड सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, रामानगरम	22	21
5.	दि प्रोग्रेसिव सिल्क रीलर्स I इंडस्ट्रियल	448	412

	कोऑपरेटिव सोसाइटी लि०, सिदलाघटा		
6.	तमिलनाडु स्टेट मल्टीइंड रीलर्स एसोसिएशन धर्मापुरी	11	4
7.	दि पैलाकोड सिल्क रीलर्स एसोसिएशन, पालाकोड	40	17
8.	कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कोयम्बटूर	68	27
9.	आंध्रा प्रदेश • आंध्र-प्रदेश में कोई संघ नहीं है।	826	350
	कुल	2512	1633

(ढ) नकद प्रवाह के वास्तविक, संभावित तथा नकारात्मक पहलू

(करोड़ ₹०)

विवरण	2000-01	2001-02
कार्यशील पूंजी कर्ज	***	***
	100	702.50
कार्यशील पूंजी मार्जिन	***	***
	100	386.34
कुल कार्यशील पूंजी	***	***
	100	605.12
निवल नियत परिसंपत्ति	***	***
	100	102.57
कुल निवेश	***	***
	100	172.87
निवल लाभ	***	***

	100	-258.98
कमी	***	-***
	100	108.60
मियादी कर्ज पर ब्याज	***	-***
	100	108.45
कुल लाभ	***	-***
	100	-219.58
निवेश पर लाभ	***	-***
	100	-619.18

घरेलू उद्योग को भारी हानि हुई है जैसाकि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है तथा निवेश पर लाभ भी नकारात्मक रहा है ।

(ज) क्षति के बारे में निष्कर्ष

6. उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी अनंतिम जांच परिणामों के पैरा (अ) के क्षति के बारे में निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं तथा दोहराते हैं कि

(क) चीन जन गणराज्य से आयात की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में इसकी खपत के संबंध में वृद्धि हुई है ।

(ख) याचिकाकर्ता के बाजार-हिस्से में गिरावट आई है जबकि आयातों में वृद्धि हुई है, जांच अवधि के दौरान आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है जिससे आगे कीमतें कम हुई हैं ।

(ग) याचिकाकर्ता के बंद स्टॉक में काफी हद तक वृद्धि हुई है ।

(घ) याचिकाकर्ता को इकाईयों बंद करने या क्षतिरहित कीमत से कम मूल्यों पर बिक्री करने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

१. कारणात्मक संबंध

कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश राज्यों के याचिकाकर्ताओं ने नए अधिक उपज देने वाले शहतूत तथा बायवोलटीन रेशम कीटों की प्रजाति पर आधारित नई बायवोलटीन प्रौद्योगिकियां अपनाई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड के उत्कृष्ट रेशम के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन नई बायवोलटीन प्रजातियों की शुरुआत से कच्चे रेशम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और क्षति का स्तर नीचे आ गया है। याचिकाकर्ताओं ने खाद्य वनस्पति, रेशम कीट बीज में सुधार तथा शहतूत की खेती और रेशम कीट पालन की पद्धतियों का पैकेज शुरू करने, उन्नत रीलिंग तकनीकों और कच्चे सिल्क के विपणन को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया है। इन प्रजातियों के साथ उत्कृष्ट कच्चे रेशम की रीलिंग के लिए बहुविध पैकेजों के आरंभ से भारतीय रेशम कीट पालन को एक नई गति मिली है।

इस नाजुक मोड़ पर रेशम कीट पालन उद्योग बड़े स्तर पर चीन से कच्चे सिल्क के पाटन का सामना कर रहा है, जिसकी कीमतें पिछले वर्षों की तुलना में अप्रत्याशित रूप से कम है और इस प्रक्रिया सिल्क का उत्पादन करने वाले रेशम के रीलरों को गंभीर क्षति पहुंच रही है। चीन के बाद, भारत विश्व में कच्चे सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कर्नाटक, जो कि रेशम कीट पालन करने वाला प्रमुख राज्य है, में 15,000 गांवों में लगभग 1,15,000 हेक्टेयर भूमि पर शहतूत की खेती होती है और लगभग 2.58 लाख परिवारों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराती है। भारत में चीन के कच्चे शहतूती रेशम के निरन्तर पाटन से संभव है कि अनुसंधान के क्षेत्र में मिली नई सफलताएं और किए गए बड़े निवेश प्रभावहीन हो जाए और रीलरों को कर्ज में फंसने के लिए विवश होना पड़े।

पाटित वस्तु के मूल्यों में अचानक गिरावट से भारतीय कच्चे रेशम के दामों में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2000-01 में पाटित वस्तुओं का आयात 3161.346 मी.टन का हुआ था जो जांच की अवधि अर्थात् वर्ष 2001-02 में बढ़कर 4929.632 मी.टन हो गया (वर्ष 2000-01 की तुलना में लगभग 55.95% की वृद्धि)। याचिकाकर्ताओं का उत्पादन स्तर 6546 मी.टन से घटकर 5663

मी.टन हो गया। वर्ष 2000-01 के दौरान क्षमता उपयोग लगभग 90% था, जो वर्ष 2001-02 के अंत तक घट कर लगभग 60% तक रह गया बिक्री की मात्रा में लगभग 40% की गिरावट आई है। कच्चे सिल्क का मूल्य सितम्बर 01 से मार्च 02 तक *** रु० से घटकर *** रु० है। जबकि वर्ष 2002-03 के दौरान कच्चे सिल्क का मूल्य का आगे और घटकर *** रु० किलो तक हो गया। अधिकांश बहुविध/काटेज बेसिन केवल 60% क्षमता पर चल रहे हैं और बहुत से बंद हो चुके हैं। चीन के कच्चे रेशम के अत्यंत कम दामों पर आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण, एककों द्वारा उत्पादित अधिकांश रेशम अनबिका पड़ा है।

जहां मांग 2000-01 में 10,664 मी.टन से घटकर 2000-01 में 9396.7 मी.टन हो गयी है, वहीं मांग में चीन से आयातों का हिस्सा 2000-2001 में 29.64% से बढ़कर 2001-2002 में 52.46% हो गया है। मांग में भारतीय घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 2000-01 में 61.39% से घटकर 2001-02 में 36.16% हो गया है। जहां घरेलू उत्पादकों की बिक्री की मात्रा में गिरावट आई है वहीं चीन से आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है। चीन से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्यों से घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य में कटौती हुई है। इस प्रकार चीन से शहतूती कच्चे रेशम के पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य दोनों का प्रभाव पड़ा है। घरेलू उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तु का स्टॉक 2000-2001 में लगभग 10% से बढ़कर 2001-02 में 40% हो गया है।

प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को चीन जनगणराज्य से हुए आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध देश भारत को शहतूती कच्चे रेशम (नंबटा हुआ) का प्रमुख निर्यातक देश है। संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि से घरेलू उद्योग को अपने क्षति रहित मूल्य से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए विवश कर दिया, जिसकी पूर्ति करने में घरेलू उद्योग असमर्थ रहा था। अतः संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी।

8. लगाया गया पाटनरोधी शुल्क

प्राधिकारी ने शहतूती कच्चे रेशम के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया है और पाटन मार्जिन से बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है जिसे यदि लगाया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो

जाएगी। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षतिरहित बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की है। चूंकि उक्त मार्जिन पाटन मार्जिन से कम पाया गया है, इसलिए प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन से कम शुल्क की सिफारिश की है।

१. अंतिम जांच परिणाम

उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:

(क) चीन जन गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शहतूती कच्चे रेशम (न बटा गया) का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(ग) वास्तविक क्षति संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण हुई है।

पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 50 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं० 50.02 तथा आई टी सी (एच एस) कोड 50020001 के तहत आने वाले चीन जन गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2एग्रेड और उससे निम्न ग्रेड के शहतूती कच्चे रेशम (न बटा गया), पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। शहतूती कच्चे रेशम (न बटा गया) की ग्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय शहतूत संघ द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ग्रेड्स के अनुसार होगी। पाटनरोधी शुल्क नीचे कॉलम 9 में उल्लिखित राशि और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा।

क्र. सं.	उपशीर्ष सं. टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विशिष्टि	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	50020001	शहतूती कच्चे रेशम(नबटा हुआ)	2ए ग्रेड तथा इसरो नीचे	चीन जन. गणराज्य	चीन जन. गणराज्य को छोड़कर कोई देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	21.97	कि. ग्रा	अमरीकी डालर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	50020001	शहतूती कच्चे रेशम(नबटा हुआ)	2ए ग्रेड तथा इससे नीच	चीन जन. गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन. गणराज्य	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	27-97	कि.ग्रा	अमरीकी डालर

10. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा तथा इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

11. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी दिनांक 20 दिसम्बर 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

12. उपर्युक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2003

Final Findings

Subject : Anti Dumping investigations concerning imports of Mulberry Raw Silk (not thrown) originating in or exported from China PR.

F.No. 14/28/2002-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof:

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed subsequent to the preliminary findings:

- (a) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified Preliminary Findings vide notification dated 20/12/2002 with regard to anti-dumping investigations concerning imports of Mulberry Raw Silk (not thrown) originating in or exported from China PR and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- (b) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the said findings within forty days from the date of the letter;
- (c) A hearing attended by the domestic industry, the Counsel for the Chinese exporters and the Embassy of China (Commercial Counsellors Office) was chaired by the Designated Authority on 4th December 2002. The fundamental deficiencies in the Chinese exporters' response was pointed out and the relevant data/information required was called for.
- (d) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 3/3/2003. The oral hearing was attended by the domestic industry, Chinese exporters, importers, user industry and the Chinese Embassy. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rejoinders, if any.

- (e) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted and arguments made by various interested parties;
- (e) The arguments raised by the petitioners and other interested parties have been appropriately dealt with in the preliminary findings and/or these findings;
- (f) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same, (submitted by the domestic industry alone) have been duly considered in these findings;
- (g) At the time of the oral hearing, the exporters were asked to negotiate on a reasonable non-injurious export price with the domestic industry and consider the possibility of a price undertaking. The domestic industry proposed a non-injurious price of USD *** + basic customs duty which was not acceptable to Chinese exporters. The Chinese companies offered a non-injurious price of USD *** + customs duty which was not acceptable to the domestic industry.
- (h) On the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioner, the Authority initiated these investigations vide Public Notice dated 17th July 2002 against dumped imports of Mulberry Raw Silk (not thrown) originating in or exported from the subject country.
- (i) Investigations were carried out for the period is 1st April, 2001 to 31st March 2002 (12 months).
- (j) Annex I- Procedures for on-the-spot investigations pursuant to Paragraph 7 of Article 6, of the WTO Agreement on Anti-Dumping states that 'As the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided or to obtain further details, it should be carried out after the response to the questionnaire has been received....' The purpose of on-the-spot investigation is therefore to verify the data already made available to the Authority and not to collect primary data. In these investigations the exporters responses were furnished by trading companies and not by the producers of the subject goods and were deficient in respect of fundamental data on cost of production and domestic sales transactions by the producers of the subject goods. Further the discrepancies in the data furnished by Chengdu Tianyou could not be subject to a verification in these investigations due to the severe threat of SARS affecting China PR.
- (k) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under investigation in the present case is Mulberry Raw Silk (not thrown), 2A grade and below originating in or exported from China PR.

Mulberry Raw Silk (not thrown) is classified under Customs sub-heading no. 50.02 of Chapter 50 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC (HS) Code 50020001. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

The Authority confirms the preliminary findings on product under consideration.

C. LIKE ARTICLES

3. In order to establish that Mulberry Raw Silk (not thrown) produced by the domestic industry is a Like Article to that exported from China PR, characteristics such as technical specifications, manufacturing process, functions and uses and tariff classification have been considered by the Authority.

The Authority also finds that there is no argument disputing that Mulberry Raw Silk (not thrown) produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported material and is substitutable by Mulberry Raw Silk (not thrown) imported from the subject country both commercially and technically. Mulberry Raw Silk (not thrown) produced by the domestic industry has been treated as Like Article to the product exported from China PR within the meaning of Rule 2(d).

The Authority confirms the Preliminary Findings on Like Articles.

D. DOMESTIC INDUSTRY:-

4. The petition has been filed by all cottage/filature/multiend silk reelers located in the states of Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh through their associations, whose details as provided in the petition are given below:-

- (a) All Silk Reelers Association, near Cocoon Market Kolar - 563101, Karnataka
- (b) Ramanagaram Silk Reelers Welfare Association, Ramnagaram, Bangalore (Rural), Karnataka
- (c) Kolar Silk Reelers Industrial Cooperative Society Ltd., Kolar
- (d) The Progressive Silk Reeler's Industrial Cooperative Society Ltd., Sidlaghatta - 562105
- (e) Karnataka State Multiend Silk Reelers Welfare Association (Regd), Main Road, Kumadan Mohalla, Ramnagaram - 571 511, Bangalore (Rural), Karnataka.
- (f) Tamilnadu State Multiend Reelers Association, No. 61-A, Krishnagiri main Road, Opp: to Government Cocoon Market, Dharmapuri - 636701
- (g) The Palacode Silk Reeler's Association, Palacode -636 808, (TN)
- (h) Coimbatore District Silk Producers Association, Coimbatore - 641014 (TN)
- (i) Dharmapuri District Silk Reeler's Association, 10/81 -C1, Electronic Estate, Hosur 635 109

The details of quantities produced by Silk producing states have been given in the petition which are as follows:-

	(A) Silk Producing States Which have been affected	Quantity (MT)	
		2000-01	2001-02
1.	Karnataka	4100	3491
2.	Tamil Nadu	355	262
3.	Andhra Pradesh	2091	1910
	Sub-total (A)	6546	5663
	(B) Other Silk Producing States		
1.	West Bengal	526	563
2.	Jammu & Kashmir	49	39
3.	Non-traditional States	95	74
	Total (A) & (B)	7216	6339

The details regarding number of members/units, number of reeling basins and unit-wise breakup of total raw silk production during the period of investigation is as follows:

	Name and address of the Association	No. of Members /Units	No. of Reeling Basins		Total Raw Silk Production (MT)
			Cottage	Multiend	
1	All Silk Reelers Association Near Cocoon Market, Kolar-563101	360	1900	300	484
2	Kolar Silk Reelers Industrial Cooperative Society Ltd. Kolar	80	580	100	153
3	Ramanagaram Silk Reelers Welfare Association, Ramanagaram	1460	9300	---	1784
4	Karnataka State Multiend Silk Reelers Welfare Association, Ramanagaram	43	---	410	75
5	The Progressive Silk Reelers I Industrial Co-operative Society Ltd. Sidlaghatta	860	5218	210	994
6	TamilNadu State Multiend Reelers Association, Dharmapuri	15	---	136	34

7	The Palacode Silk Reelers Association, Palacode	57	340	---	84
8	Coimbatore District Silk Producers Association, Coimbatore	95	568	---	142
9	Andhra Pradesh • AP does not have any associations	1176	6920	840	1912
	TOTAL	4145	24826	1996	5663

The petitioners account for 89.33% of the total domestic production of the subject goods in the country and therefore satisfy the standing to file the present petition.

The Authority notes therefore that the petitioners constitute “domestic industry” and have the required standing to file the present petition under the Rules.

E. Other Issues:-

- I.** A hearing attended by the domestic industry, the Counsel for the Chinese exporters and the Embassy of China (Commercial Counsellors Office) was chaired by the Designated Authority on 4th December 2002. The fundamental deficiencies in the Chinese exporters response was pointed out. In their written submissions, they had modified the cost of production provided by Chengdu Tianyou Silk Co., Ltd., without giving any reasons or substantiation. As the respondents are traders, they had provided their average domestic purchasing price and average price at ex-factory level for exports without giving supporting documentary evidence and details of adjustments claimed. The Authority noted that transaction-wise data on domestic sales could be provided only by the manufacturers of the subject goods who had sold the product in the Chinese domestic market to such traders and to others.

II. Views expressed by importers prior to and in the Public Hearing held on 3rd March 2003:-

The Authority notes that none of the importers have filed a response to the importers questionnaire.

(A) Shah Silk and Fabrics Pvt. Ltd.:

1. The investigations has been carried out in a discriminate manner whereby a better quality of silk yarn when imported does not attract anti dumping duty while cheaper quality product (grade 2 A and below) attracts anti dumping duty. The cost difference is Rs. 665/- per kg more for grade 2A.
2. The domestic producers of cocoons are small time farmers who carry their produce to various centres for sale where reelers in private sectors as well as political controlled who operatives by their produce at prices at their wills and whims.
3. If the quality and prices of the Indian produce are good enough to sustain our local and international requirement why Indian weavers should go to China or other countries for their requirements. The reeling technology adopted the world over has still not been adopted in India. A better produce comes out of better cocoons and better reeling. It is

true that since over 10 years the Central Silk Board has developed bivoltine varieties of cocoons with better yields. The cost of Indian silk is more because we are still using the age old reeling technology. As admitted by the petitioner they produce even today only a quality of 2A grade and less. Normally Indian silk is being used as a warp yarn for making dupion fabrics only. Whereas today with availability of Chinese, Brazilian and other origin raw silk, Indian weavers are weaving better quality fabrics and are exporting to various countries and that to competing with Chinese Fabrics exporters.

4. The value added Indian Silk Export will definitely suffer because of anti dumping proposals. If the weavers are to weave these sarees with high cost of the yarn the consequent effect is that the cost of the sarees will also go up.
5. Anti dumping duties will bring in unemployment to thousands and lacks of weavers in the unorganised sector in India and cannot be termed as in larger interest.
6. Anti dumping duties will open up increased smuggling.

(B) The Indian Silk Export Promotion Council:

We are not against farmers rearing silk, they need protection from cheap imports. That is precisely why we were not objecting per-se to the imposition of this duty, if cheap imports affect the sericulture industry. This representation has become necessary because the anti-dumping duty rate has been fixed at an abnormal level, which actually leads to ruin the silk weaving industry, and subsequently exports. In fact, we expected an increase of 5% to 10% in the customs duty on mulberry raw silk to safeguard the local sericulture industry. But, this abnormal hike has put a spoke in the production process. We understand the entire power loom silk weaving industry - 50,000 in Karnataka which supplies silk fabrics to domestic market and silk merchant exporters, is drastically affected which is going to create unemployment problem. Apart from Karnataka, the silk power loom weaving industries in Gujarat, Andhra Pradesh, Tamilnadu and Uttar Pradesh are increasingly feeling the impact of this notification and their ruin is very much on cards.

Indian produces about 15,000 tonnes of mulberry raw silk, bulk of which is gradeless and not of such quality which can be used for producing fabrics on power looms both for domestic and export market. The yarn produced out of Indian Raw Silk can be used only on handloom. As against the production of 15,000 tonnes of mulberry raw silk, we have a demand of 25,000 tonnes per annum leaving a shortfall of 10,000 tonnes which need to be imported. If imported mulberry raw silk is kept at a very high price it will act as a deterrent to imports, but the local industry will be flooded with smuggled mulberry raw silk by unsocial elements and that will result in the loss of revenue. The import price fixed at US \$ 33.19 as anti dumping rate is totally arbitrary and unjustifiable because at this price nowhere in the world even MRS of 3A Grade and above quality are not being sold.

(C) Varanasi Vastra Udyog Sangh

1. Prices of Domestic yarn have gone down to lack of demand, because of Imports of Silk Fabric from China at cheaper rates, which is below, even, our cost of production. Production of Domestic Yarn has gone down due to the same reason. Closing Stock has also gone up because of import of cheap silk fabrics from China. Import of China Silk Yarn (Not Thrown) has gone up due to greater demand in export market & powerloom

industry of the Fabrics manufactured by Imported Raw Silk Yarn of Not Thrown (untwisted) quality.

2. When Import of Raw Silk was allowed under S.I.L. on 30.10.1998, import of Raw Silk below 2A grade only was put under banned list. It was because of the reason that yarn of 2A and above grade is not produced in India and, as such, there is no competition of domestic yarn with Grade 2A & above that is being imported. Secondly, the yarn 'not thrown' produced in India can only be used after twisting. It cannot at all, be used in 'not thrown' condition like Chinese yarn. Manufacturing of export & powerloom fabrics in India is of 'not thrown' (untwisted) quality only.
3. The anti-dumping duty imposed shall result in an increase in price of over 80%, which is a steep hike. 2A yarn was being imported at the invoice value of Dollar 13 to 14 which after adding 35% custom duty comes to Dollar 19. It has been increased to Dollar 33.19. Now after paying anti-dumping duty the price in market will go up to Rs. 1700/- per Kg., instead Rs. 950/- per kg. The market price has already increased by Rs. 250/- merely on the announcement of Anti-Dumping Duty.
4. The Production & Consumption of Domestic Silk Yarn has gone down, as already explained above, not due to Import of Chinese Silk Yarn. It has gone down due to import of low priced silk fabrics from China. Hence Indian manufactures are not in a position to compete with Imported Silk Fabrics, which are also of far superior quality, because our cost is the same as that of Imported Silk Fabrics. For example current booking of 60 gm. Imported Crepe Silk is Dollar 1.40 which after adding 30% customs duty comes to Rs. 90/- per meter, same as the cost of Silk Fabrics produced by us, by using domestic yarn. If there is no manufacturing of silk Fabrics how will the sericulture grow? If we manufacture Silk fabrics (Crape 60 gm. Quality) with imported Chinese Raw Silk Yarn, cost of Raw Material alone will be Rs. 136/- after Anti-Dumping Duty as against Rs. 92/- of Imported Ready Chinese Silk Fabrics.
5. Varanasi & entire eastern region of Uttar Pradesh is dependent on Banarasi Fabrics Production - Over 5 lakh families are employed in it. It is a rural based cottage industry. It is a fully self financed industry, with no financial help from central or state government to export base is very solid. More than 75% of silk fabrics being exported are manufactured in Varanasi. 50% of imported Chinese silk yarn is consumed in Varanasi alone. Rest of India consumed only 50%. Due to Anti-Dumping Duty both Handloom & Powerloom Industries will suffer in Varanasi. It may be noted here that 90% of Domestic Production is consumed by Karnataka alone.

(D) Karnataka State Weavers Central Committee; M/s Mysore Powerloom Silk Manufacturers Cooperative Society Ltd.; M/s Chamundi Textile (Silk Mills Ltd.); Bangalore District and Bangalore Rural District Powerloom Weavers Production and Sales Cooperative Federation Ltd.

1. The Authority has treated Indian Mulberry Raw Silk without reference to any grade as like article. It is a well known fact that there is no gradation system in India. Differences

in quality of Chinese and Indian Silk are numerous and are very well known. Majority of Indian production is multi-voltine variety where as Chinese production is that of bi-voltine variety. When the Indian silk is used in powerlooms, due to frequent breakages in the yarn, productivity comes down quite significantly. Such frequent breakages are due to lack of consistency and strength in the Indian yarn as compared to the Chinese yarn.

2. It is a well known fact that the Indian domestic industry has never manufactured raw silk equivalent to grades 2A and above. In the past imports of raw silk below 2A grade alone were prohibited and imports of 2A grades and above were allowed freely.
3. Mulberry Raw Silk imported from China is used primarily in powerlooms whereas the Indian Silk is primarily used in handlooms. Chinese raw silk can never be used for manufacturing the famous Indian silk sarees as the Chinese silk lacks lustre and sizing. Chinese silk is used for manufacturing organza and Indian silk is not used for manufacturing organza.
4. With regard to injury, the petitioners have stated that the total production has come down from 6546 MTs to 1566 MTs. This is an agricultural related product. Production of cocoons is closely linked to the production of mulberry plants. This aspect has not been examined at all.
5. The petitioners have claimed that most of the plants were running at 60% capacity and some of them are closed. No evidence has been submitted alongwith the application in this regard. This is a claim without any basis.
6. They have not furnished any details regarding inventories, cost of sales, profit, loss, investments, net worth, employment, etc. They have even stated that there is no change in demand.
7. The Authority has determined a reference price of USD 33.19/kg which is not only arbitrary but astronomical.
8. There are more than 6 to 8 lakh powerloom weavers whose livelihood is at stake. The domestic industry has never supplied them the raw silk of required quantity and quality. The domestic industry has been supplying principally to handloom weavers. Powerloom weavers were not their market. In this case, if the duties could not be reduced, at least duty of goods imported for the purpose of using in powerlooms shall be exempt. In any case the reference price needs to be brought down to realistic level.

Rejoinder:

1. We reiterate our submissions that the Indian domestic industry has never manufactured raw silk equivalent to grades 2A and above. Bivoltine variety production by the domestic industry was too low and commercially insignificant. It is an undisputed fact that the Chinese raw silk and Indian silk are entirely two different products with different enduses.
2. The petition gives macro level data relating to domestic production, sales, etc. In addition, the petitioner should have given individual unit wise data as well as a consolidated data of all the petitioners.

(E) Silk Trade Association (Regd.) Varanasi

1. In the powerloom and handloom industry in Varanasi, Raw Silk in Not Thrown (untwisted) condition is used for which Chinese quality proves to be good as the quality of domestic Raw Silk is not fit for the same.

2. The raw silk (not thrown) produced in India is generally used after twisting. It is not possible and viable to use it in NOT THROWN condition like the Chinese Raw Silk.
3. Many powerlooms and handlooms will come to a complete halt for want of regular good quality Chinese raw silk. Already several looms, which used to produce silk fabrics (crepe 60 gms quality) are lying idle due to import of Chinese Silk Fabrics.
4. The resent price of Chinese Raw Silk is around USD13-USD 14/kg. So this steep import duty of above USD20/kg will provide adequate margin for the smugglers and the smuggling will again flourish which is neither in the interest of the trade nor in the interest of government.
5. The yarn thus imported will also be of inferior quality, supplies will be irregular and there will be wide price fluctuations. This will make calculations of price difficult and will hinder execution of direct and indirect export orders of silk fabrics, sarees and made-ups.
6. There is not going to be any benefit to domestic sericulture industry also for whose benefit this duty has been imposed. The growth of domestic sericulture has not been hindered because of Chinese Silk Yarn but because of import of low priced silk fabrics from China, which is freely importable now. The domestic quality of raw silk was mainly used in these fabrics and since the same is now freely importable in India and is of better quality and low priced the production of these fabrics dwindled in India. Since the manufacturing of silk fabrics, which were produced using domestic silk yarn, has reduced it has hampered the growth of sericulture in the country and the imported raw silk is in no way hampering its growth.

F. Pure Silk Weavers Association :

1. We are an apex organisation consisting of Pure Silk Yarn Twisters, Silk Fabric Weavers, Dyers, Local Weavers Associations and Silk Co-operative societies catering to the needs of over 5,000 power looms. Most of our members supply silk fabrics to domestic market as well as to silk exporters.
2. To begin with, we want to make a point very clear, we are not against farmers rearing silk, they need protection from cheap imports. That is precisely, we were not objecting "per-se" the imposition of this duty, if cheap import affect the sericulture industry. This memorandum has become necessary when the duty rate has been fixed at an abnormal level, which actually leads to ruin the silk weaving industry.
3. This abnormal hike has put a spoke in the production process. The entire power loom silk weaving industry - 50,000 in Karnataka & 5000 Loom in Gujarat, and about 25000 Loom in up-West Bengal, Bihar etc. in which supplies silk fabrics to domestic market and silk merchant exporters has come to a halt which is going to create unemployment problem. Apart from Karnataka, the silk power loom weaving industries in Gujarat, Andhra Pradesh, Tamilnadu and Uttar Pradesh are increasingly feeling the impact of this notification and their ruin is very much on cards.

G. Federation of Indian Art Silk Weaving Industry:

1. The indigenous prices have come down on account of increase in production and quality as a result of R & D and not on account of low price.
2. As against a total of 16000 tons of silk produced in the country, the current domestic demand is 23000 tons leaving a huge gap in demand and supply to the extent of 7000 metric tons.

3. The demand-supply gap in mulberry raw silk exists basically for warp-grade silk for powerlooms. Warp-grade silk preferred by powerlooms can usually be had only from bi-voltine races and is being met by imported Chinese bi-voltine silk.
4. There are more than 30000 powerlooms and 180000 handlooms in the country using pure silk yarn for manufacturing fabrics. In the production of pure silk fabrics, 6 handlooms is equal to 1 powerloom. The production of both the sectors is almost equal. Both the sectors employ more than one million workers. On account of anti-dumping duty, these powerlooms will stop production and the workers will be thrown out of employment.

III. Views expressed by Exporters in the Public Hearing held on 3rd March 2003:-

The views of each Chinese exporter has been reported in detail in the Preliminary Findings from Para 4(A) to 4 (Q). The Chinese exporters filed their written submissions on 27th May, 2003, and requested for condonation of delay on account of out break of SARS in China:

1. At the outset it would be useful to explain the process by which silk yarn is made. The Silk Worms consume Mulberry leaves and through a natural biological process produce Cocoons. The sericulturists extract Cocoons, which they sell in the market to the Silk Reelers. The Silk Reelers in turn, make the yarn out of the Cocoons. The costs associated with the making of yarn are as under:

For obtaining 1 Kilogram of Silk Yarn 6.5 Kilograms of fresh Cocoons are required, thus, Cost of 6.5 Kilograms of fresh Cocoons @ Rs. 125 per Kilogram	Rs. 810
Cost of Reeling	Rs. 340
Total	Rs. 1,150
Less: sale proceeds of by-products/wastage	Rs. 350
Balance unabsorbed cost	Rs. 800
Sale price of 1 Kilogram of Silk Yarn	Rs. 1,000
Profit to the Silk Reeler	Rs. 200

A perusal of the above data would demonstrate that the bulk of the cost of Silk Reelers is comprised of the cost of Cocoon. The direct costs incurred by the Silk Reelers are recovered out of the sale of by products/wastage and thereafter the Silk Reelers make a profit of Rs. 200 per Kilograms.

It is submitted that Cocoon is not a manufactured product, it rather grows naturally. The Silk Reelers therefore merely perform job work and value added services to convert the Cocoon into silk yarn. It would therefore be apparent that a mere change in physical characteristics of Cocoon takes place when the Cocoon is converted into silk yarn while the chemical composition of the product remains the same. It is submitted that a mere physical change does result in manufacture of goods. Reliance in this connection is placed on the judgement of the Supreme Court in CST (Dy) vs. Pio Food Packers, 1980 Supp. SCC 174. It is, therefore, submitted that silk yarn being basically and essentially a natural product and not a manufactured product, cannot form the basis of the present anti-dumping proceedings.

It is further submitted that the mere fact Silk Reelers make a healthy profit of more than 17% on its cost, is indicative of the fact that there is no injury to the Silk Reelers that can form the basis of these proceedings.

Chinese silk is qualitatively different from the domestically produced silk. Chinese silk is made from dried cocoon while Indian silk is made from fresh cocoons. The technology adopted by the Chinese exporters is far superior from that adopted by the domestic industry which results in substantial difference in the quality of the silk yarn so much so that while the Indian silk can only be used by handloom industry, the Chinese silk yarn is suitable for weaving on powerlooms. It has been a cause of complaint of the importers that there are frequent breakages in yarn when the Indian silk yarn is used in the power looms.

It is submitted that the demand for raw silk in India is 25,000MT out of which 15,000 MT is made available by the domestic industry resulting to a shortage of 10,000 MT which is met through imports.

IV (A) Views expressed by Domestic Industry in the Public Hearing held on 3rd March, 2003-

1. We thank the Designated Authority for its Preliminary Findings dated 20th December, 2002 and we accept the contents the Preliminary Findings of the Designated Authority in toto. However, we would like to make as an additional submission "that all the Exporters and Importers from China PR or who are sourcing from China PR should be treated as operating in Non-Market Economy as per the provisions of Annexure I, Paragraphs 7 & 8 of the Anti Dumping Rules, as amended on 15.7.1999 and 31.5.2001."
2. The Domestic Industry would like to reiterate that continued dumping of Chinese Mulberry Raw Silk has led to the serious material injury and is likely to negate the research break-through achieved and which would ultimately lead the reelers into debt traps as they have made huge investments in the Domestic Industry.
3. Quantum of Imports -
 - (a) The increase in the total imports of Mulberry Raw Silk from China PR was 60.57% in the POI as compared with the quantum of imports in 2000-2001.
 - (b) The share of China PR in total imports was 91.68% in 2000-2001 and 93.93% in 2001-2002 (12 months - I).
4. Petitioners contend:-
 - (i) The domestic industry has suffered material injury during the POI.
 - (ii) There is an imminent threat of material injury to the domestic industry.
 - (iii) The basic indicator of the health of the industry is the profitability, which is continuously on the decline and currently has turned into losses. This is consequent to the average price of the articles from the subject countries which is continuously on the decline since 2000-2001 and has now reached abysmal levels leading to surge in volumes.
 - (iv) There is a single market where dumped Chinese imports compete head-to-head with the product of Indian mills. Price determines the choice of the supplier.

- (v) Head-to-head competition and prior econometric examination of competition among a very wide range of international sources of the subject goods reveal that the imports and domestic goods are highly substitutable.

5. Sales and market share:-

- (i) Sales of the Petitioner have declined by 48.09% as compared to the previous year.
 - (ii) Total Domestic Sales have declined by 44% (approx.) (43.54%) as compared to previous year market and of the Domestic Industry by 48%.
 - (iii) Share of Domestic Industry has declined from 62% to 35% i.e. almost by 27% as compared to previous year.
 - (iv) Market share of dumped imports have increased from 30% to 54% as compared to previous year.
 - (v) Market share of dumped imports in total demand have increased from 32% to 57% as compared to previous year.
 - (vi) The volume and market share of dumped imports in relation to total consumption of the article in India have doubled in a span of one years and there is now a surge in volume of imports from the subject countries at further reduced prices:
- (a) Market share of indigenous industry has increased at the cost of profitability.
 - (b) Dumped imports have increased in absolute terms as compared to total sales, consumption and production.
 - (c) Imports from subject countries continue to increase even after POI and pose a threat of injury (in fact already injured) to the domestic industry.

6. Effect of dumped imports on prices:-

- (a) The average prices of dumped imports from the subject countries have declined by 40% and continue to decline further. The domestic producers have a stark choice - either to follow these prices down or lose market share. Domestic producers had no option but to opt for the former to keep their capacity utilisation from falling to ruinous levels.
- (b) (i) Average domestic net sales realisation have declined.
- (ii) Whilst the average cost of production of Domestic Industry increased net sales realisation declined during the same period.
- (iii) Net sales realisations of Domestic Industry has declined drastically as a result of customer requirement to meet low prices of imported goods, the industry has now turned losses i.e. it is not even able to recover total cost of production.

The addition to the market of dumped imports forces the market price down significantly. Current inventory growth indicates that prices will have to fall even lower before they stabilize for Indian producers if subject imports do not increase further. But with increasing volumes of subject imports, prices cannot stabilize, and instead prices will be lower and further lower and continue to follow a downward spiral. This is conclusively proved by the fall in prices of the article from the subject countries.

- (c) With declining prices the domestic producers were faced with increase in costs during this period.

Indian producers are caught in a devastating cost-price squeeze. They must follow the declining prices at the very time the costs of every indigenous producer is rising. This is not just price suppression, but even more injurious price depression.

7. The increase in inventory of the domestic industry directly as a result of sharp decline in Average CIF prices of imported product from the subject countries, which has resulted in;
 - (a) loss of market share and indigenous sale by the domestic industry because of the sale of the subject imported dumped products in the domestic market at exorbitantly low price.
 - (b) Price suppression has prevented 'price increase' which has ultimately led to lower sales realisation by the domestic industry.
 - (c) Under utilisation of capacity by domestic industries.

8. Impact on Profitability:

There has been :-

- (a) decline in net sales realisation;
- (b) an increase in the cost of production which could not be passed on to the consumers;
- (c) the increase in volumes, coupled with decrease in CIF prices of the article from the subject countries, and consequent decline in domestic selling prices and increase in cost of production have resulted in the profitability of the domestic industry crashing, and is at the verge of closure;
- (d) The above facts indicate that the dumped imports and its lower prices have resulted in a crash in profitability and have threatened the very survival of the domestic industry.

9. Production and Capacity Utilisation:-

- (a) The production of domestic industry during the POI has declined by almost 14% (13.48%) as compared to the previous year.
- (b) The capacity utilisation has declined by 30% as compared to the previous year.

10. Closing Stocks:-

Closing stock has increased by almost 300% as compared to the previous year.

11. Normal Value:-

Domestic industry have time and again submitted that most sales transactions in China are amongst Government companies. Raw silk is largely produced by Government units only. Hon'ble Authority has rightly examined this claim of the petitioner in the light of para (7) and (8) of Annexure I of the Anti-Dumping Rules as amended.

The Authority has noted that information in the relevant Appendices of the questionnaire regarding cost of production and domestic sales have not been submitted by the Chinese companies. Neither have they submitted information/evidence regarding the criteria for rebutting the presumption of a non market economy as per sub para (3) of para 8. The Authority further notes that since the data on cost of production and domestic sales has not been submitted, a determination on normal value as per provisions contained in Section 9 A (I) © (1) and (ii) read with sub rule 2 (I) and (ii) of Annexure 1 of the Anti Dumping Rules cannot be made and failed to satisfy the test enshrined in paragraph 8, Annexure J to the Anti

Dumping Rules as amended, they should be treated as manufactures or exports from non market economy. For claiming market economy status/individual treatment, the exporter or manufacturer needs to satisfy all the parameters as enshrined in paragraph 8 Annexure 1 failing which, they would be treated as operating under non market economy. A copy of judgement of EU imposing an anti dumping duty on imports of ferro molybdenum from PRC has been enclosed.

The traders in any case cannot claim market economy status and a copy of the EU imposing a provisional anti dumping duty on imports of glycine from PRC has been enclosed wherein the EU has stated that three claims were rejected "because the companies concerned did not produce the product under consideration. They claimed that they purchased low purity glycine on which they performed a production process which, however, did not change either the chemical composition or the physical characteristic of the product under consideration. As such, they resembled traders of the product under consideration. As only producers can obtain market economy status their claims had to be rejected. "

12. Export Price:

We accept the finding of the Designated Authority with regard to the export price. The ex-factory export price has been determined after taking the adjustments as claimed by the exporters. After considering the adjustments as claimed the weighted average ex-factory export price for individual exporters has been arrived.

Rejoinder and subsequent submissions filed by the Domestic Industry:

1. **Interchangeability/commercial substitutability of Imported and Domestically produced 'Like Articles'** It is a misrepresentation of facts to say that Chinese silk is used only on powerlooms whereas the Indian silk is used only on handlooms. To say that the Chinese raw silk alone can produce organize is irrelevant, since very little quantities organize is produced in the country. Indian Multiend silk & filature silk which is of warv quality is used in many power loom clusters of the country. Karnataka Silk Industries Corporation (KSUC) which markets its famous 'Mysore Silks' uses extensively Indian raw silk on its power looms. Indian multiend reelers in particular supply Indian raw silk to many exporters who manufacture power loom fabrics. At the same time Indian handlooms in major hand loom clusters like Hindupur, Dharmavaram (AP), Salem, (Tamilnadu) Molakalmuru (Karnataka) have started using Chinese silk extensively. Thus both imported and domestic silk yarn are indeed like products which can be interchanged depending upon the price. During the last two years Chinese silk has replaced the Indian silk in many power looms & handlooms because the Chinese companies have brought down the prices of their raw silk to very low levels making it commercially difficult for manufacturers of Indian silk yarn to compete.
2. **Production of Bivoltine silk in the domestic industry:** The Chinese silk is being imported in to the country not because it is Bivoltine silk but due to the supply demand gap in the country. Since both Chinese bivoltine silk and Indian Multi-bivoltine silk are also used to manufacture similar products, import of Chinese raw silk into the country at unprecedentedly low prices has damaged Indian industry. In recent times India had also

made substantial investments under the plan schemes and various projects to boost the production of Bivoltine silk. The Chinese companies consider this as a threat and have resorted to dumping silk at low prices to nip the Indian Bivoltine silk production at the bud stage itself. Chinese silk has been imported into India for many years. Only now there have been complaints of dumping by the Chinese companies. We would like to reiterate that the quantum of Chinese raw silk imports have risen from around 3000 to 7000 tonnes (2002-03) only because of the dumping resorted to by the Chinese companies.

3. **Yarn of 2A and above grade:** There is no evidence of any kind to show that the majority of Indian manufacturers need 2A or higher grades of silk. All the same the Government of India has liberalized the Import-Export Policy & there are no restrictions on import of these grades in to the country. All grades of silk are welcome as long as the exporting companies do not resort to dumping & hurt the local industries. Therefore price is the only issue to be considered. Raw silk (Not thrown) i.e. not twisted cannot be used directly whether it is Chinese raw silk or Indian raw silk. It is technically incorrect to say that the Chinese raw silk can be used without twisting. Basically to withstand the stress & strain during loom operation twisted raw silk is a must whether it is Indian or Chinese origin.
4. **Demand:** Though there is a demand supply gap in silk for many years there is no reason to assume that the gap is 10000 MT. While Chinese imports have been hovering around 2000 to 3000 MT over the years it has crossed 5000 MT from the year 2001 onwards and it has touched 7000 MT during the year 2002-03. During this period many manufacturers have switched over to Chinese silk due to its abundant availability at very low prices. The domestic industry is badly hurt with the prices plunging from the levels of Rs. 1500 per Kg. to below Rs. 1000 per kg. during the last two years. Similarly Chinese silk prices which was around 26 US \$ CIF Indian ports without (Customs Duty) a few years back have declined to less than 14 US \$ during the last couple of years. If demand for Chinese silk alone was the factor there would have been no need to bring down prices which shows that Chinese companies have resorted to dumping with malafide intentions.

B) Quality Sericulture Service Club:

1. Quality Sericulture Service Club is a registered Non-Governmental Voluntary Organization established to create a common platform for the sericulturists, silkworm seed producers, silk reelers and silk interest for discussing measures to improve quality standards of their produce, creating greater opportunities for gainful employment in rural areas rationalisation of sericultural practices achieving quality upgradation of the produce.
2. India is the second largest producer of mulberry raw silk in the world next only to China. Sericulture is a vital agro based, rural cottage industry that can generate massive employment. It is estimated that one hectare of mulberry plantation can create direct employment to 12 to 13 persons throughout the year. Apart from labour intensive nature, sericulture is the most suitable rural industry for the under privileged and landless labourers. The Industry is particularly suited to small and marginal farmers who grow their own mulberry and undertake silkworm rearing.
3. Now, of late the sericulture practices have changed its way from traditional to non-traditional and rationalized practices. Huge investments have been made by the individual sericulturists on land, irrigation, plantation and buildings to rear new varieties of bivoltine

cocoons capable of providing 2A+ grade International silk with the joint co-operation and efforts of the Sericulture Department, Central Silk Board and Japanese International Co-operation Agency (JICA).

4. Though these new races are suitable for temperate climate, we have been successfully rearing these races in Tropical Climate with adoption of necessary technology during favourable season from August to March. By this, it is possible to produce International grade of 2A and above silk from the cocoons of this race. These races are gaining momentum and popularity among the Sericulturists of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
5. It is a fact that out of China's total production hardly 10% is used for internal consumption and the balance 90% has to be exported to make sericulture industry economically viable. But in our country, the situation is quite opposite. The entire silk production is totally consumed locally and are able to consume imported raw silk.
6. There was a steep decline in the income margins and towards the end of 2002 the Sericulture Industry started showing negative returns. This being the case and with the background of reasonable investment made added with the targeted production of improved races, the price crash resulted in most of the sericulturists uprooting their mulberry gardens, which led to unemployment of about 2,73,000 persons in Karnataka alone.
7. Based on various representations the Designated Authority after detailed investigations passed an interim order recommending imposition of anti dumping duty on mulberry raw silk (not thrown) of 2A grade and below followed with the Customs Notification dated 2nd January, 2003. Immediately after this Notification cocoons prices started recovering the loss. It is alarming to note that during 2001, the total import of silk was about 4,730 MT and during 2002 it was about 6,795 MT (+ 42%). During 2001, the total silk fabric export was to the extent of 530.21 million US dollars but during the year 2002 it was 469.22 million US dollars and hence there is a decline of 8.35% in the exports (Detailed statement enclosed Annexure-3). It is obvious from the above statements, that the silk imported to the country during the year 2002 is diverted locally for a premium. These figures reveal that there is no justice for the huge and cry of these importers.
8. India's strength in textile is in handloom which is depending on local multivoltine silk (Ex: Kanchi, Arni, Dharmavaram, Kancheepuram, Molkalmuru etc.,). The local handloom units engaged in production of silk fabric are consuming multivoltine silk for our traditional dress material. Due to free availability of gradeless imported silk, these units have started consuming and blending with our multivoltine silk causing great injury to the traditional fabric.
9. We would also like to draw your immediate intervention, the fact of deliberate attempts to circumvent your orders dated 20th December, 2002, by the exporters in China, categorising virtually all their export to India as of 3A and higher grades. This is a serious violation of the norms and we request to impose anti dumping duty on all grades of silk imported from other countries. Advance licensing scheme where imports are used for re-export alone may be considered for duty exemption and not imports under DFRC and DEPB where the duty free silk goes into the domestic market to depress prices.

(C) Views of Director of Sericulture, West Bengal

1. The ongoing slump in the cocoon and silk market which has reached an alarming level in recent past is a matter of serious concern to all sericulture practising states, West Bengal in particular. This state, because of its proximity to neighbouring countries, has become the worst victim of the situation arising out of the indiscriminate flooding of Chinese silk which is evident from the declining trend in the price of cocoons vis-à-vis raw silk. With the unprecedented crash in the price of cocoons, there has been a trend amongst a good number of rearers to uproot their mulberry garden and to switch over to other agriculture crops posing a threat to the very existence of this age old traditional agro based cottage industry.
2. Imposition of anti-dumping measures is a very justified, appropriate and well-timed move initiated by the Government of India which needs to be continued in future. As a positive outcome of this approach, there has already been an increasing trend in the market in the price of indigenous cocoons and raw silk which is expected to bring back the confidence, morale and encouragement amongst the sericulturists.
3. Smuggling of foreign silk from across the border of the neighbouring countries would continue unabated unless the law enforcing authorities ensure stringent measures against this illegal trade.
4. Different new technologies and package of practices evolved by Sericulture Research Institutes of CSB are being implemented in the field to improve the productivity and product quality which would hopefully help the sericulturists to fetch a remunerative price for their produce in the years to come.

(D) Examination by the Authority on Submissions made by all interested parties:

The Authority has examined the issues raised by all interested parties which have mainly centered on the questions of grade of raw silk being imported, substitutability of Chinese and Indian yarn, level of demand and prices of imported Chinese raw silk. The Authority notes that there are no restrictions on imports of various grades into the country. As far as the present investigations are concerned the scope of the product under investigations has been restricted to 2A grade and below only. In the course of the last two years, Chinese silk has been used in both powerlooms and handlooms due to availability at a very low prices. Further, raw silk cannot be used without twisting, i.e. in 'not thrown' condition, irrespective of origin.

The demand for raw silk was approximately 9,400 MT during the period of investigations and the supply demand gap was around 3,700 MT only. The Authority notes that imports of the subject goods from China have been higher at 4,930 MT which has further increased to 5,293 MT during April 2003 to January, 2003 (10 months) in the post investigation period. Chinese cif prices for the subject goods have declined from Rs. ***/kg in the POI to Rs. ***/kg in the post POI period (i.e. by 22%). Considering the weighted average landed price at approximately Rs. ***/kg, the Authority notes that raw silk was being imported at this price by users of the subject goods.

5. (E) Comments on Disclosure Statement from Interested Parties

The comments on the Disclosure Statement from M/s Chamundi Textiles Ltd., silk weavers societies, Silk Trade Association, Varanasi Vastra Udyog Sangh and others all of whom are importers of the subject goods has been received. Some of the issues raised have been dealt with in Para (D) above.

- (i) They have noted that the Authority has proposed to limit the scope of the investigation to 2A grade and below only.
- (ii) They have noted that the Authority has rejected the questionnaire response of all the 17 respondent exporters and has proposed to determine normal value and dumping margin based on best information available. They have requested the Authority to kindly take note of the obligations cast upon the Authority in terms of Paragraph 7 of Annex II of the WTO Agreement.
- (iii) They have noted that the dumping margin and methodology followed in arriving at the same has been indicated in detail in the Disclosure Statement. They have requested for a disclosure of the elements that have been considered while arriving at the NIP giving the basis and details of each item of cost that have been included in arriving at the NIP.

(F) Examination by the Authority on Comments received on Disclosure Statement

- (i) The product under investigation in the present case is Mulberry Raw Silk (not thrown), 2A grade and below originating in or exported from China PR.
- (ii) The Authority notes that normal value determination has not been based on a secondary source or on information supplied in the petition but on the information available on the estimated cost of production in the country of origin plus selling, administrative and general expenses and a reasonable amount of profit after making reasonable adjustments which has been taken as the basis for working out the Normal value of the subject goods in China PR.
- (iii) Since the Non-Injurious Price is based on cost components which are confidential to the domestic industry disclosure of the basis and details of each item of cost is not possible.

F. DUMPING:-**1. Exporters and Producers of the Subject Goods in the Country of Origin:-**

The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject country in terms of section 9 A (1). The Authority notes that the exporters in China PR who have submitted information in response to the exporter's questionnaire are not the manufacturers/producers of the product under consideration but are only exporters/traders. The details of domestic sales as per Appendix 1 and the cost of production of the subject goods required to be furnished as per formats in Appendix 8, 9 and 10 of the exporters questionnaire have consequently not been furnished in their responses. Therefore response to the exporters questionnaire is deficient in respect of vital appendices.

The Authority has noted in the Preliminary Findings that the response to the exporters questionnaire has been furnished by trading companies who have no production facilities for the manufacture of the subject goods. These companies have requested for market economy treatment. A total of 11 out of the 17 respondents from China PR in this case have described themselves as state owned companies. However, the information in the relevant appendices of the questionnaire regarding cost of production and domestic sales had not been submitted by these companies. Neither had they submitted information/evidence at the time of the preliminary findings regarding the criteria for according market economy treatment as per sub-para (3) of para 8. Since the data on cost of production and domestic sales were not submitted, a determination on normal value as per provisions contained in Section 9A (1) © (I) and (ii) read with sub-rule 2 (i) and (ii) of Annexure 1 of the Anti-Dumping Rules could not be made and the Authority was constrained to proceed as per 'facts available' in the preliminary findings.

In order to allow exporting producers from China to submit a claim for market economy treatment, the Authority sent a Market Economy Treatment questionnaire to all the 17 respondent companies to enable them to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of the Anti-Dumping Rules as amended. Detailed questions regarding ownership, management, control, determination of commercial and business policies and on financial situation were addressed to these companies. The respondents were also requested to provide complete supporting documentary evidence for the cost of production of Mulberry Raw Silk and furnish all transaction wise domestic sales in the domestic market in China PR during the period of investigation by producers of the subject goods in China as per format set out in Appendix 1 of the exporters questionnaire i.e., Information Relating to Sales in Home Market. The Authority examined the responses received from 13 of these respondents to determine whether these companies enjoyed a degree of independence from the State and operated in market conditions comparable to that which would prevail in a market economy country.

The information furnished shows that 9 out of the 13 respondents to the MET questionnaire are State-owned companies. While the respondents have stated that there are no government officials in the companies which are state owned, no details have been furnished on the actual share holders. Although it stresses on the principle of separation and managerial authority, it is not clear how the enterprise can utilise and dispose of property which is state owned and the responses do not establish how the state does not interfere in the business operations of these companies.

Out of the 13 respondents to the MET questionnaire, 5 trading companies have given no information on producers; in the case of the remaining 8, some information in respect of producers has been given. With the exception of 2 trading companies (Chongqing Golden Silk and Jiangsu Soho) and their producers, the rest are all state-owned. Therefore the absence of state interference cannot be guaranteed. In the case of the aforesaid 2 companies, domestic sales have either not been reported or the names of buyers have not been disclosed. For the remaining six companies, with the exception of Chengdu Tianyou, the others have either not reported domestic sales or have given incomplete information with regard to domestic sales and have also not furnished their cost of production. In the absence of data on cost of

production as required under Appendix 8 of the exporters questionnaire, it is not known if such sales have been made in the ordinary course of trade. The domestic sales information in the case of Sichuan New Century Industries Co., Ltd., a co-operating producer of the subject goods shows that all sales have been made to the affiliate/sister company, viz., M/s Chengdu Tianyou. The exporter did not submit data indicating that the sale to the affiliate was in the ordinary course of trade and at an arms length.

The Authority notes that the producers have not responded to the exporters questionnaire and while information relating to domestic sales has been furnished in some cases by the producers in response to the market economy treatment questionnaire, the information submitted is only with respect to sales made to the related/affiliated exporter or the buyers names are not disclosed. It is not known if all domestic sales transactions during the period investigated are covered. Since data on cost of production as required under Appendix 8 of the exporters questionnaire has not been provided by these companies it is not known if such sales have been made in the ordinary course of trade.

The Chinese trading companies who have responded to the exporters questionnaire and subsequently to the Market Economy Treatment questionnaire have requested for market economy/individual treatment. However these companies were unable to sufficiently establish absence of State interference as far as exports prices, quantities and terms and conditions of sale to India through such state-owned trading companies. The costs of major inputs/utilities do not appear to reflect market values as they are procured from either collectively owned or state-owned companies. In some responses, the quantities sold in the domestic market and the rates per unit of the subject goods were largely uniform. The method of procurement of raw materials and utilities and volumes sold and prices thereof do not satisfy the criteria laid down in sub paragraph (3) of Paragraph 8, Annexure I. Further, the capital of most of these companies is owned by the state. Therefore from the submissions made by the trading companies/producers it is not conclusively established that these companies operate independent of the State authorities and in response to market signals; if they are free to decide on prices, costs and inputs, including raw materials, and whether the costs of major inputs substantially reflect market values; if decisions regarding cost of technology and labour (salaries and number of employees), level of production, pricing, investment and on the quantities sold in the domestic and export markets are made in response to market signals reflecting supply and demand. In some cases it has been stated that there is no mandatory provision for these companies to have their financial statements audited every year. Their statements are not required to be subjected to audit in view of the small scale and nature of business involved. From the responses received, a determination on whether the companies meet the requirements specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, could not be made.

(A) NORMAL VALUE

The views of each Chinese exporter has been reported in detail in the Preliminary Findings from Para 4(A) to 4 (Q). However, the information in the relevant appendices of the questionnaire regarding cost of production and domestic sales have not been submitted by these companies. Only a single exporter, M/s Chengdu Tianyou Silk Co. Ltd., a limited liability company set up in accordance with the Company Law of the People's Republic of

China holding the majority shares of Sichuan New Century Silk Industries Co., Ltd. a producer of the product concerned, furnished information concerning sales, while data on production costs were prepared by Sichuan New Century. M/s Chengdu Tianyou and its affiliate producer Sichuan New Century Silk Industries Co., Ltd. subsequently also responded to the MET questionnaire.

**Examination of market economy treatment questionnaire response by Chendu Tianyou/
Sichuan New Century Silk Industries by Authority**

1. Chengdu Tianyou, a limited liability company, has 19 shareholders. Chengdu Tianyou Development Co, Ltd., holds 50% of the shares while the rest are held by natural persons. Sichuan New Century Silk Industries the producer, is stated to be a fully private-owned limited liability company. The list of shareholders show that while Chengdu Tianyou holds 66.7% of the shares, 33.3% is held by a state-owned company.
2. The producer has furnished information on the major suppliers of raw material during the period of investigation. These include cocoon farmers (85% procurement); a private company (8.7% procurement); 3.7% procurement from a company whose nature/status is undisclosed; and 2.6% procurement from a state-owned company. The method of procurement is stated to be spot transaction. The producer purchases the fresh-cocoon from cocoon farmers and then dries the fresh cocoons to dry-cocoons.
3. As regards utilities, the major supplier of electricity was a state-owned company against a long-term contract. The unit cost of electricity is RMB *** yuan/kw/h. Water is pumped from the river by lift pump and the electricity is stated to have been calculated in the cost. The producer produces steam by coal which is said to have been calculated in the cost. The unit costs of water and steam have not been furnished. Coal is procured against a long term contract from a private enterprise. The per unit value of coal is stated to be RMB *** yuan/MT.
4. The number of employees is stated to be *** out of whom *** persons are skilled and unskilled workers; *** are management personnel and *** are managers. The average salary is RMB *** in a year.
5. Information has been furnished on domestic sales made by the producer in the home market. The total volume sold is *** MT of a value of *** RMB which is RMB ***/MT. The Authority notes that all these sales have been made to affiliate/sister company, M/s Chengdu Tianyou and are credit sales. Hence these are sales not in the ordinary course of trade as they are not arms length transactions.
6. The Authority recalls its Preliminary Findings as regards determination of normal value. In the preliminary findings, the Authority noted that the cost of production claimed is USD ***/kg. In the cost of production, the total quantity of cocoons used (***kg) for total production of *** kg works out to *** kg per unit (kg) of output. This renditta level is unusually low as compared to the best achieved Indian renditta level of *** kg per unit (kg) of output. The Authority notes that the cocoon cost as per data submitted accounts for 71.3% of the total cost of production and the consumption level claimed is unusually low. Subsequently to the Preliminary Findings, the Authority notes that the company has provided cost of production data for the period July 2001 to March 2002 which is not the period of investigation. The Authority notes that the average domestic sales price in the domestic market in China PR is USD ***/kg which is below the cost of production claimed

by the company and hence domestic sales transaction have not been in the ordinary course of trade.

7. The data on cost of production and domestic sales as submitted by Chengdu Tianyou and its producer at the time of the preliminary findings (in response to the exporters questionnaire) and thereafter in response to the Market Economy Treatment questionnaire has been examined as per the table below :-

1.	As submitted in response to exporter's questionnaire 2.	As submitted in response to MET questionnaire 3.	Difference in data as submitted in exporters response and MET response 4.
Production: July 2001 to March 2002 (Kg)	*** (All grades)	*** concerned product	- 178441
Cocoons Procured/ Consumed (kg)	***	***	***
Cocoon rate /RMB/Kg	***	Not available	Not available
Renditta Level	***	***	***
Raw Material Cost	***		
Direct Labour (RMB)	***	***	***
Direct Labour (per kg RMB)	***	***	***
Utilities (water, electricity and coal) RMB/kg	***	Although average price of electricity is stated to be RMB ***/kw/h, the consumption of electricity required per/kg of raw silk is not stated. The average price of coal has been indicated as RMB ***/MT but the consumption of coal/kg of raw silk is not stated. rates and consumption	Not available

		of water not given.	
Conversion Cost	RMB *** /kg		
Depreciation	***	***	***
Depn RMB/kg	***	***	***
Financing cost Including interest	***	Not available	Not available
Packing costs	***	Not available	Not available
Selling cost	***	Not available	Not available
Admn. Costs	***	Not available	Not available
Cons. Tax., Sales Tax	***	Not available	Not available
Total cost	RMB ***		
Profit	RMB ***		
Selling Price	RMB *** USD ***		

The Authority notes that the production in volume terms and renditta level claimed by the company was *** kg and *** respectively at the time of the Preliminary Findings and *** kg and *** respectively in response to the MET questionnaire. No supporting evidence in respect of each of the cost components have been furnished. The Authority notes that there are serious discrepancies in the data furnished which could not be subject to a verification in these investigations due to the severe threat of SARS affecting China PR.. However the Authority notes that the domestic sales price of Chengdu Tianyou for the subject goods is below the cost of production claimed and hence is not in the ordinary course of trade. The domestic sales of the producer have moreover been made to its affiliate company i.e., Chengdu Tianyou and are hence not arms length transactions. The Authority is therefore constrained to reject the data provided on the cost of production by Chengdu Tianyou/ Sichuan New Century for all the aforesaid reasons.

The Authority notes that since the data on cost of production and domestic sales has not been submitted by the other 16 respondents in these investigations and since in the case of M/s Chengdu Tianyou/ Sichuan New Century Silk Industries, the cost of production data is unacceptable for the aforesaid reasons, a determination on normal value as per provisions contained in Section 9A (1) © (I) and (ii) read with sub-rule 2 (i) and (ii) of Annexure 1 of the Anti-Dumping Rules cannot be made. The Authority is therefore unable to apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 and is constrained to proceed as per 'facts available'.

Under the circumstances, Normal Value under the rules is determined on the basis of 'facts available' as per Rule 6(8). Therefore, the information available on the estimated cost of production in the country of origin plus selling, administrative and general expenses and a reasonable amount of profit after making reasonable adjustments has been taken as the basis for working out the Normal value of the subject goods in China PR which is therefore

considered to be USD ***/kg or Rs ***/kg at an average exchange rate during POI of 1USD=Rs.47.54.

(B) EXPORT PRICE

At the time of preliminary findings, the Authority had determined individual dumping margins for the respondents from China in these investigations. The Authority notes that as per Sl. 5 of the 'General' Section of the Exporters Questionnaire evidence is to be attached wherever any claim has been made, particularly with regard to the price adjustments claimed from the normal value and export price. However the data furnished by the exporters was not substantiated with relevant evidences. The Authority further notes that as per official data the total quantity of imports from China is far higher than that reported by Chinese exporters. The Authority has therefore been constrained to determine the export price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8).

The ex-factory export price has been determined after considering the following adjustments as claimed by one of the exporters under Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.

Packing RMB ***/kg = USD ***/kg
 Inland freight RMB ***/kg = USD ***/kg
 Storage RMB ***/kg = USD ***/kg
 Handling RMB ***/kg = USD ***/kg
 Discount/commission- USD *** or USD ***/kg
 Insurance-USD *** or USD ***/kg
 Ocean freight- USD *** or USD ***/kg

As per official DGCIS data available with the Authority, a quantity of 49,29,632 kg of the subject goods of a cif value of Rs *** was exported by China PR during the period of investigation (April 2001 - March 2002). The cif price is therefore Rs ***/kg. The Authority has determined the ex-factory export price after considering the adjustments as claimed above. The ex-factory export price therefore works out to USD ***/kg.

(C) Dumping Margin:-

Given the constructed normal value at USD ***/kg and the ex-factory export price at USD ***/kg the dumping margin is USD ***/kg (which is 47.89% of the export price).

G. INJURY:-

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such article..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by

the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from the subject country are more than the limits prescribed in Rule 11 Supra.

The Authority called for costing information from the Domestic Industry represented by various reelers association, in the state of Karnataka, Tamil Andhra Pradesh etc. in the prescribed proforma for the period under investigation and for the previous years. The actual cost of production of the subject goods for the domestic industry has been used to determine the cost of production on the basis of Generally Accepted Principle (GAAP).

In the determination of NIP for the Domestic Industry the Authority has made proper analysis of all the relevant factors including usage of raw materials, usage of utility, the actual expenses during the POI, investment, the capacity utilization etc. to arrive at a Non Injurious Price for the Domestic Industry. NIP for the domestic industry has been determined considering a reasonable profit margin on the capital employed.

For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, quantum of sales, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the rules supra, the details of which are given below:-

(a) Quantum of Imports

Source: DGCIS

	2000-2001	2001-2002 (12months-POI)
Individual country imports (MT)		
China PR	3161	4929.632
Subject Country (Total)	3161.346	4929.632
Other sources (total)	286.815	393.317
Total imports (MT)	3448.161	5322.949

The increase in the total imports of Mulberry Raw Silk from China PR was 55.95% in the POI as compared with the quantum of imports in 2000-2001.

The share of China PR in total imports was 91.68% in 2000-2001 and 92.61% in 2001-2002 (12months-POI).

As per DGCIS data compiled for the period April 2002 - January 2003, the quantum of imports from China PR was 52,92,722 kg of a value of Rs 384,09,00,873 indicating a further significant decline in the cif price at Rs 725.69/kg in the post investigation period.

(b) Production and Capacity Utilisation

The production capacity, actual production and capacity utilisation of the petitioners was as follows: -

Petitioners	2000-2001	2001-2002 (12months-POI)
Installed Capacity (No. of basins)	25,456 basins	26,822 basins
Installed Capacity (MT)	7255	8408
Production (MT)	6546	5663
Capacity Utilisation%	90% approx.	60% approx.

The details of number of members/units, number of reeling basins and total raw silk production during the period of investigation is as follows:

	Name and address of the Association	No. of Members /Units	No. of Reeling Basins		Total Raw Silk Production (MT)
			Cottage	Multiend	
1.	All Silk Reelers Association Near Cocoon Market, Kolar-563101	360	1900	300	484
2.	Kolar Silk Reelers Industrial Cooperative Society Ltd. Kolar	80	580	100	153
3.	Ramanagaram Silk Reelers Welfare Association, Ramanagaram	1460	9300	---	1784
4.	Karnataka State Multiend Silk Reelers Welfare Association, Ramanagaram	43	---	410	75
5.	The Progressive Silk Reelers I Industrial Co-operative Society Ltd. Sidlaghatta	860	5218	210	994
6.	TamilNadu State Multiend Reelers Association, Dharmapuri	15	---	136	34
7.	The Palacode Silk Reelers Association, Palacode	57	340	---	84
8.	Coimbatore District Silk Producers Association, Coimbatore	95	568	---	142
9.	Andhra Pradesh	1176	6920	840	1912

	• AP does not have any associations				
	TOTAL	4145	24826	1996	5663

(c) Sales and Market Share

	2000-2001	2001-2002 (12months-POI)
Sales of Petitioners	6546	3397.8 (fallen by 48.09% approx)
Sales of other domestic producers	669	676
Total Sales	7216	4073.8
Demand	10,664	9396.7
Share of domestic industry in demand	61.39%	36.16%
Share of imports in demand	32.33%	56.64%%
Share of dumped imports	29.64%	52.46%

It is seen that dumped imports have increased in absolute terms. While the market share of imports from China PR have increased in demand the share of the domestic industry has declined in demand.

(d) Price undercutting and price depression

Year	Sales Realisation (Rs/kg)	Rs/kg	
		China PR	Others
2000-2001	***	***	***
2001-2002 (POI)	***	***	***
Post POI (2002-03)	***	***	

It is evident from the above table that the exporters from China PR have reduced their prices significantly in the POI. The domestic industry has been forced to reduce its selling prices to respond to the low import prices in the market.

(e) Profitability:-

Petitioner	2000-2001	2001-2002 (12months-POI)
COP	***	***
Selling Price	***	***
P/L	(***)	(***)

The petitioners losses have increased in the period of investigation.

(f) Closing stocks:-

		(Kg)
	2000-2001	2001-2002 (12months-POI)
Petitioner	10%	40% (2265.2 MT approx.)

(g). Actual and potential decline in sales

As stated earlier, the domestic sales volume came down from 6546 MT in 2000-01 to 3397.8 (fallen by 48.09% approx) during the POI. Thus, there was a significant decline in sales volumes.

(h) Productivity

In the last decade the renditta (quantum of cocoons consumed to produce 1kg of raw silk) which is an indicator of productivity has declined from 12 to 7, thus enhancing the competitiveness of the domestic industry. This is because of the introduction of highly productive new races by research institutions into the field. However due to the availability of cheap Chinese silk in the market there has been huge uprooting of mulberry and reduction of mulberry acreage during and after the period of investigation.

(i) Output

The output of the domestic industry was 6546 MT during 2000-01. It came down to 5663 MT units during POI.

(j) Factors affecting domestic prices

The market for raw silk is highly competitive. Globally, China PR is the major producer and has been quoting rock bottom prices to various customers in India. The domestic industry is required either to quote still lower prices or lose the sales volume. Unfortunately, the domestic industry is not in a position to reduce the prices to the levels of the imported subject goods. Therefore, it is losing sales volumes quite significantly and many units have been forced to close down. Mulberry farms have also been uprooted and farmers have moved away from sericulture to other activities. There is no other factor that has affected domestic prices to a significant extent.

(k) Magnitude of the margin of dumping

The dumping margin for the subject goods is 47.89%. Therefore, the magnitude of the margin of dumping is significantly high and has caused severe injury to the domestic industry.

(l) Employment and Wages

Around 1633 units were closed during the POI and 2500 units during post POI. Thus around 20000 man days were lost during POI and 30000 man days during post POI.

(m) Growth and ability to raise capital

There are no signs of vitality in the domestic producing units. The sales volumes of the domestic producers have fallen due to dumped imports. The domestic industry is not able to raise any significant capital since the crisis continues even in the post POI period.

The number of reeling units under the various reelers associations which have closed in the POI is as follows:

	Name and address of the Association	No. of Units functioning	No. of Units closed
1.	All Silk Reelers Association Near Cocoon Market, Kolar-563101	240	120
2.	Kolar Silk Reelers Industrial Cooperative Society Ltd. Kolar	55	25
3.	Ramanagaram Silk Reelers Welfare Association, Ramanagaram	802	658
4.	Karnataka State Multiend Silk Reelers Welfare Association, Ramanagaram	22	21
5.	The Progressive Silk Reelers I Industrial Co-operative Society Ltd. Sidlaghatta	448	412
6.	TamilNadu State Multiend Reelers Association, Dharmapuri	11	4
7.	The Palacode Silk Reelers Association, Palacode	40	17
8.	Coimbatore District Silk Producers Association, Coimbatore	68	27
9.	Andhra Pradesh • AP does not have any associations	826	350
	TOTAL	2512	1633

(n) Actual, potential and negative aspects of cash flow

(Rs in Crore)

Particulars	2000-01	2001-02
Working Capital Loan	***	***

18406I/03-10

	100	702.50
Working Capital Margin	***	***
	100	386.34
Total Working Capital	***	***
	100	605.12
Net Fixed Assets	***	***
	100	102.57
Total Investment	***	***
	100	172.87
Net Profit	***	-***
	100	+258.98
Depreciation	***	***
	100	108.60
Interest on Term Loan	***	***
	100	108.45
Total Returns	***	-***
	100	-219.58
Return on Investment	***	-***
	100	-619.18

The domestic industry has incurred huge losses as can be seen from the table above and return on investment has been negative.

H. CONCLUSION ON INJURY

6. In view of the foregoing the Authority confirms the conclusions on injury at Para J of the Provisional Findings and reiterates that:-

- the quantum of imports from China PR have increased in absolute terms and in relation to consumption in India;
- the market share of the petitioner has gone down while that of imports has increased; imports have continued to increase in the post investigation period with further decline in price;
- the petitioners closing stocks have increased significantly;
- the petitioners have been forced to close down or sell at prices below their non-injurious price.

The Authority therefore concludes that the domestic industry has suffered material injury.

7. Causal Link

The petitioners in the states of Karnataka, Tamilnadu, Andhra Pradesh have adopted new bivoltine technologies based on new high yielding mulberry and bivoltine silkworm races resulting in enhanced productivity and quality silk of international grade. The introduction of these new bivoltine races has increased the raw silk yield considerably with renditta levels coming down. The petitioners have laid emphasis on the improvement of food plants, silk worm seeds, introduction of package of practices for mulberry cultivation, improved techniques in reeling and rationalisation of marketing raw silk. These races coupled with the

introduction of multiend package for reeling of quality raw silk had given a new momentum to Indian Sericulture.

At this critical juncture the sericulture industry is faced with large scale dumping of Chinese Raw Silk at prices which are inexplicably low when compared to earlier years and in the process causing severe injury to the silk reelers producing raw silk. India is the second largest producer of raw silk in the world next only to China. In Karnataka, a premier sericulture state, around 1,15,000 hectares are under mulberry cultivation distributed in 15,000 villages providing gainful employment to about 2.58 lakhs families. The continued dumping of Chinese Mulberry Raw Silk in India is likely to negate the research breakthroughs achieved and the huge investments made and force the reelers into debt traps.

Due to abrupt decline in the prices of the dumped goods prices of Indian raw silk has come down considerably. During the year 2000-01 the imports of the dumped goods were to the tune of 3161.346 MT which has increased significantly to 4929.632 MT during the period of investigation i.e. 2001-02 (an increase of around 55.95% over the year 2000-01). The petitioners production declined from the level of 6546 MT to 5663 MT. The capacity utilisation during the year 2000-01 was around 90%, which has gradually reduced to around 60% by the end of the year 2001-02. There is decline of about 40% in sales volume. The domestic raw silk prices declined sharply from the level of Rs. *** to *** from Sept '01 to March '02. While, during the year 2002-03 the raw silk prices further declined to Rs. ***/kg. Most of the Multiend/Cottage Basins are only running at 60% Capacity and many are closed. Most of the silk produced by the units are lying unsold due to easy availability of Chinese raw silk at very low prices.

While demand has come down from a level of 10,664 MT in 2000-2001 to 9396.7 MT in 2001-2002, the share of Chinese imports in demand has risen from 29.64% in 2000-2001 to 52.46% in 2001-2002. The share of Indian domestic producers in demand has declined from 61.39% in 2000-2001 to 36.16% in 2001-2002. While the sales quantum of domestic producers has fallen the share of imports from China has increased. The landed values of the subject goods from China have undercut the average selling price of the domestic industry. Thus there is both volume and price effect of dumped imports of Mulberry Raw Silk from China. The stocks of the subject goods with the domestic producers has increased from approximately 10% in 2000-2001 to 40% in 2001-2002.

The Authority holds that the material injury to the domestic industry has been caused by imports from China PR.. The subject country is the major exporter of Mulberry Raw Silk (not thrown) to India. The increase in the market share of imports from the subject country forced the domestic industry to sell below its non-injurious price which resultantly, the domestic industry was unable to recover. The material injury to the domestic industry was therefore caused by the dumped imports from the subject country.

8.Anti-Dumping duty imposed:-

The Authority has carefully evaluated the injury caused to the domestic industry on account of dumping of Mulberry Raw Silk and has recommended the amount of anti-dumping duty equivalent to the dumping margin or less, which if levied, would remove injury to the

domestic industry. For this purpose, the Authority has compared the non-injurious selling price of the domestic industry with the landed value of imports from the subject country. As the margin is found to be less than the dumping margin, the Authority has recommended duty lower than the dumping margin.

9. FINAL FINDINGS:-

The Authority after considering the foregoing, concludes that:

- (a) Mulberry Raw Silk (not thrown) originating in or exported from China PR has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) material injury has been caused by imports from the subject country.

10. It was decided to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. Accordingly, it is proposed that definitive anti-dumping duties be imposed on Mulberry Raw Silk (not thrown) of 2A grade and below, originating in or exported from China PR, falling under customs sub-heading no. 50.02 of Chapter 50 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC (HS) Code 50020001. The grading of Mulberry Raw Silk (not thrown) shall be as per the internationally accepted grades approved by the International Silk Association. The anti-dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in Col.9 and the landed value of imports.

Sl. No	Sub-Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country Of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	50020001	Mulberry Raw Silk (not thrown)	2A grade and below	China PR	Any Country Other than China PR	Any Producer	Any exporter	27.97	kg	USD
2.	50020001	Mulberry Raw Silk (not thrown)	2A grade and below	Any Country Other than China PR	China PR	Any Producer	Any exporter	27.97	kg	USD

11. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

12. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 20th December 2002.

13. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority